



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]
No. 883]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2009/ज्येष्ठ 13, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2009/JYAISTHA 13, 1931

पर्यावरण और बन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1392(अ).—कालेसर राष्ट्रीय उद्यान चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और हरियाणा की सीमा पर अवस्थित है, यह शिवालिक पहाड़ियों की तराई में आता है, इसकी सीमाएं दो विभिन्न राज्यों के दो संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश की सिम्बलबाड़ी बन्यजीव अभ्यारण्य और पूरब की ओर से उत्तराखण्ड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बंटा है और कालेसर बन्य जीव अभ्यारण्य कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व-पश्चिम के पास है तथा इस प्रकार दोनों के बीच कोई भौतिक अवरोध विद्यमान नहीं है और संपूर्ण क्षेत्र में वनस्पति और पशु प्रजातियां बहुतायत में हैं तथा इनका ऐतिहासिक, आर्थिक और औषधीय महत्व है तथा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप जीव-जन्तु बहुतायत में हैं जिसके अंतर्गत लम्बी पूँछ वाले गिरगिट, भारतीय राक पायथन, किंग कोबरा, कामन करेत, रेड स्नेक, सेल वायपर, पिट वायपर आदि भी हैं;

और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) और खण्ड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर गुलान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को 'पर्यावरणीय संवेदनशील जोन' (जिसे इसमें इसके पश्चत् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और बन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में $30^{\circ} 16' 00''$ से $30^{\circ} 28' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 26' 00''$ से $76^{\circ} 36' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपबंध -के पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

चिकन, कुंसली, खिल्लानवाला, बागपत, भागेरी, खिजरी, नागल पट्टी मिल्क, चांदपुर बुखेवता, ताजेवाला, (गुटरेन)चिकन, अम्बवाला, तिबरीयान, रयानवाला, झांडु ओड, फैजपुर गरही, कालेसर, मोहम्मदुवास।

(iii) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजरेत दिनांग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्युग्म ग्राम स्थापनां, दरों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को ऐर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनरांछ्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपर्दर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और ऐसा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयाँ :-

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(III) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पांच सौ मीटर से सात सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच सौ मीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (II) कालेसर सांस्कृतिक उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रवंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।
- (ज) जल :-
- भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
 - जल के रांदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
- (च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हारियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।
- (छ) बहिस्त्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्त्राव निर्गमन नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्त्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।
- (ज) ठोस अपशिष्ट :-
- ठोस अपशिष्ट के व्ययन का फ़िल्हाल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रवंध और डुथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।
 - जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिनाक्त खाद बनाकर या कृगि खेटी के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत शीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिह्नित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (रांझण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विश्वात चयित होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और रथानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन पालक (प्रादेशिक), यमुनानगर, सदस्य-सचिव ;
- II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;
- III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ;
- V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

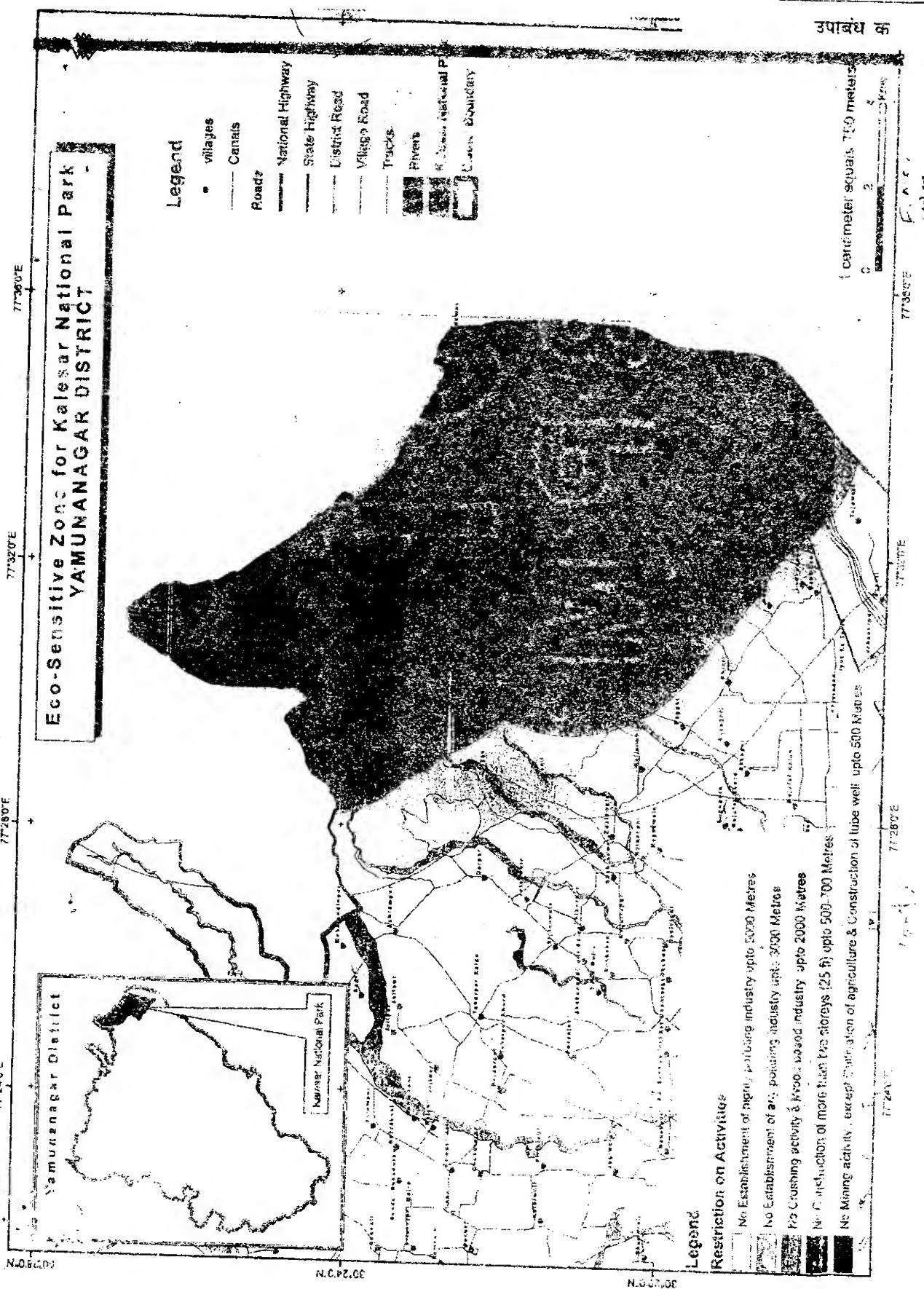
(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आन्तित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपर्युक्त



**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1392(E).—WHEREAS, the Kalesar National Park is located on the junction of the four states viz. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Haryana, it falls in Shiwalik foot hills, it shares boundaries with two protected areas of two different states namely the Simbalbarha Wildlife sanctuary of Himachal Pradesh towards the North and Rajaji National Park of Uttrakhand towards the East and Kalesar Wildlife Sanctuary is just towards the East-West of Kalesar National Park and as such there does not exist any physical barrier between the two and the entire area is very rich in plant and animal species and have historical, economic and medicinal significance and the Kalesar National Park is rich in reptilian fauna which includes large monitor lizard, Indian rock python, King cobra, common krait, Red snake, Russel viper, Pit viper etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

- 1. Boundaries of Eco-sensitive Zone** – (i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar National Park situated in the Yamunanagar District of Haryana between $30^{\circ} 16' 00''$ to $30^{\circ} 28' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 26' 00''$ to $76^{\circ} 36' 00''$ East longitude.

- (ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Kalesar National Park in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Chickan, Kansli, Khilanwala, Bagpat, Bhageri, Khizri, Naggal Patti Milk, Chandpur, Baumbewala, Tajewala, (Gutrian) Chikan, Ambwala, Tibriyan, Rayanwala, Jhandu Oad, Faizpur, Garhi, Kalesar, Mohammaduwas.

- (iii) All activities in the Kalesar National Park are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone-

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.
- (III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Kalesar National Park.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Kalesar National Park upto a distance of five hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between five hundred meters to seven hundred meters from the boundary of Kalesar National Park, construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- (I) Mining upto five hundred meters shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.
- (II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- I. Deputy Conservator of Forests (Territorial), Yamunanagar as the Member Secretary;
- II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
- III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
- IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar;
- V. Senior Town Planner of the area;

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

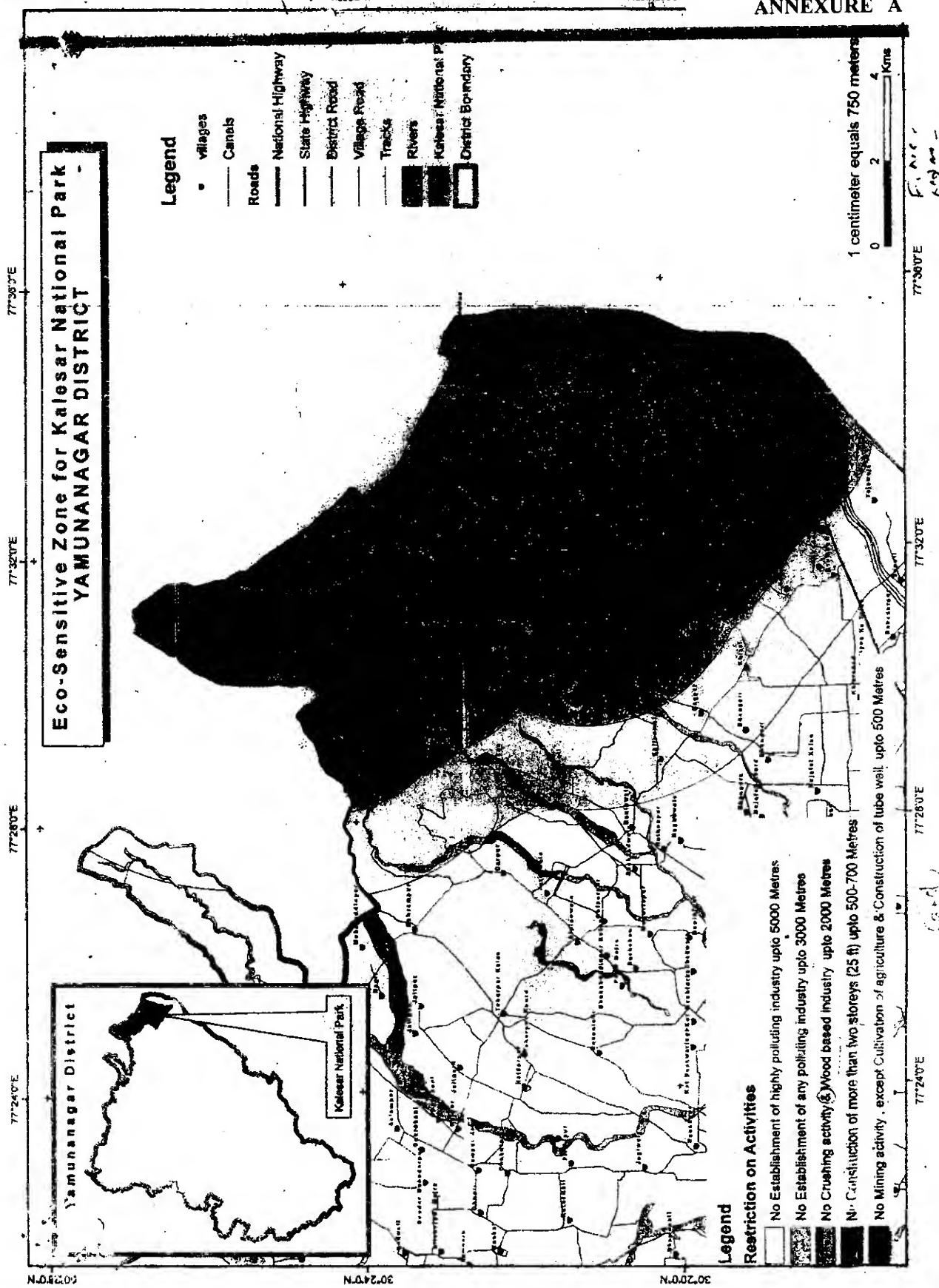
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1393(अ).— कालेसर वन्य जीव अभ्यारण चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और हरियाणा की सीमा पर अवस्थित है, यह शिवालिक पहाड़ियों की तराई में आता है, इसकी सीमाएं दो विभिन्न राज्यों के दो संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् उत्तर की ओर हिमाचल प्रदेश की सिम्बलबाड़ा वन्यजीव अभ्यारण और पूरब की ओर से उत्तराखण्ड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में बंटा है और संपूर्ण क्षेत्र में वनस्पति और पशु प्रजातियां बहुताय में हैं तथा इनका ऐतिहासिक, आर्थिक और औषधीय महत्व है।

और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा।

प्रात्मक प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (1) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में $30^{\circ} 16' 00''$ से $30^{\circ} 28' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $77^{\circ} 20' 00''$ से $77^{\circ} 37' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है।

(2) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

सालेमपुर, बहादुरपुर, गोहराबनी, राजपुर, रामपुर जाट, छोती, चबूतरान, कटारवाली, पीरथीपुर, जोगीवाला, मानकपुर, अर्जन मजरा, लैहा, लालहारी खुर्द, मणीपुर, दादौपुर जटन, घिसरपरी, लेडा खदीर, कोटरा खानसिंह, हाफिजपुर, मुहावतीवाल, तिब्बी, तोहन, बलोहल्प, बकारवाला, बहानगेरा, बहानगेरी, मौजाफत खुर्द, खिजराबाद, सतियोन, कारालो, बहादरपुर, कोतीपुर (किशनपुर) देकरीवाला, नैनावाला, सपोती, बरिनागली, नगला, मुहजुदीनपुर, जतिपुर, हैदरपुर, तहारपुर कलन, बंसंतौर, शहाबुद्दीनपुर खुर्द, मजारा, बच्चन, मुक्रीबपुर, कोट, मुशीरका धकवाला, दौलतपुर, अहमदपुर, कोट सरकारी, बहरामपुर, दारपुर, जटानवाला, सिपैनवाला, चिम्बोरपुर, शहजादवाला, बनीवाल, नाथनपुर, मोगीवाला, खिल्लानवाला, बागपत, खिजरी, नागल पट्टी, मिल्क, चांदपुर, बुम्बेवला, ताजेवाला, कयानवाला, झाँडु गड, तिबरीयान, अम्बवाला, फैजपुर, कालेसर मोहम्मदुवास, गरही, चिकन, कंसली, गुटरेन चिकन।

(3) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, 'शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए

परिवर्तित करना लब के सिवाय जोनल मार्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपर्कितेन विद्यमान स्थानीय जनसंघों के प्राकृतिक विद्यास के साथ विद्यमान स्थानीय गिवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मार्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी दिनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिशित करने के लिए विवार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मार्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मार्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और उन मंत्रालय द्वारा उत्तराधिकारी अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैसा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, यिहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(ल) औरोपीय इलाइयां :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण दीरी रीगा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काल्ड आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की रीगा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अन्तरिक की विमाओं के नलकूप वैंकर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच अन्य वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्तरन और खनन :-

(I) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्मावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) व्यनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्त्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्त्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्त्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय रवीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है।

(2) मानीटरी समिति दस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विद्युत व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रवंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

I. उप वन पालक (प्रादेशिक), यमुनानगर सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ;

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यस्त गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ;

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ;

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्विधित होंगे।

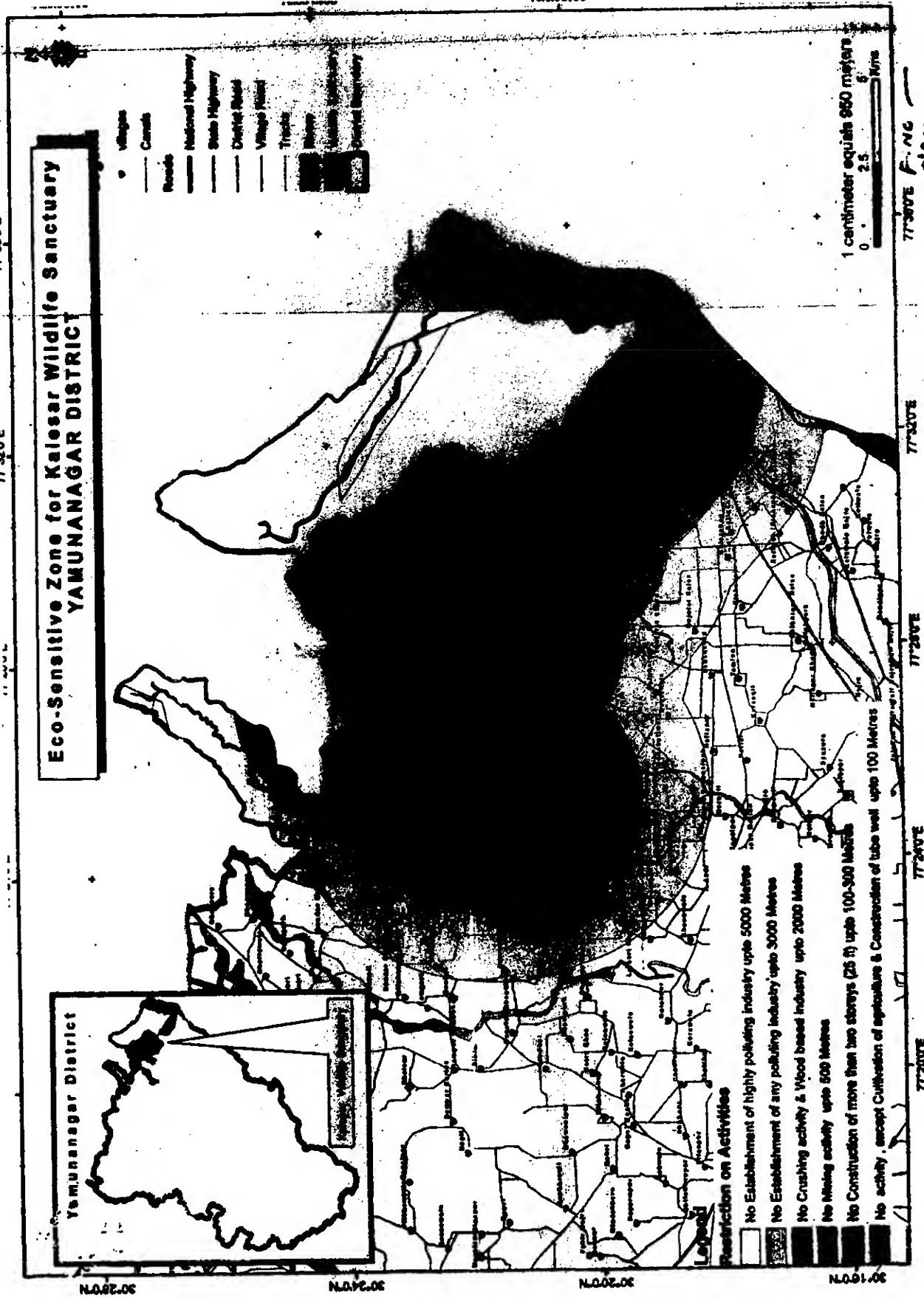
(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विमांगों या रांगांगों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय रागय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईमजेड]
डॉ. जी. ची. सुग्रेमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1393(E).—WHEREAS, the Kalesar Wildlife Sanctuary is located on the junction of the four states viz. Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Haryana, it falls in Shiwalik foot hills, it shares boundaries with two protected areas of two different states namely the Simbalbarha Wildlife sanctuary of Himachal Pradesh towards the North and Rajaji National Park of Uttrakhand towards the East and the entire area is very rich in plant and animal species and have historical, economic and medicinal significance.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(1) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary situated in the Yamunanagar District of Haryana between $30^{\circ} 16' 00''$ to $30^{\circ} 28' 00''$ North latitude and between $77^{\circ} 20' 00''$ to $77^{\circ} 37' 00''$ East longitude.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Salempur, Bahadurpur, Gohtabani, Rajpur, Rampur Jat, Chholi, Chabutaron, Katarwali, Pirhipur, Jogiwala, Manakpur, Arjan Majra, Laiha, Lalhari Khurad, Manipur, Dadupur Jatan,

Ghisarpuri, Leda Khadir, Kotra Kahansingh, Hafizpur, Muhabaliwala, Tibbi, Tohn, Balohalp, Bakarwala, Bhangera, Bhangeri, Mujafat Khurd, Khizrabad, Satiyon Karalao, Bahadarpur, Kotipur (Kishanpur), Dekriwala, Nainawala, Sapoti, Barinagli, Nagla, Muhajuddinpur, Jatipur, Haiderpur, Taharpur Kalan, Bansantaur, Shahabuddinpur Khurd, Majara, Bachchan, Muquribpur, Kot Mushiarka Dhakwala, Daultpur, Ahmadpur, Kot Sarkari, Bahrampur, Darpur, Jatanwala, Sipianwala, Chimboporut, Shahzadwala, Baniawala, Nathapur, Mogiawala, Khilanwala, Bagpat, Khizri, Nagal Patti, Milk, Chandpur, Barnubewala, Tajewala, Kayanwala, Jhandu Gad, Tibriyon, Ambwala, Faizpur, Kalesar, Mohammaduwas, Garhi, Chikan, Kansli, Gutrian Chikan.

(3) All activities in the Kalesar National Park are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.

- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone-

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.
- (III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Kalesar Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Kalesar Wildlife Sanctuary, construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- (I) Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary.
- (II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(b) Solid Wastes:- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- I. Deputy Conservator of Forests (Territorial), Yamunanagar as Member Secretary;
- II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India;
- III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India;
- IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar;
- V. senior Town Planner of the area;

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

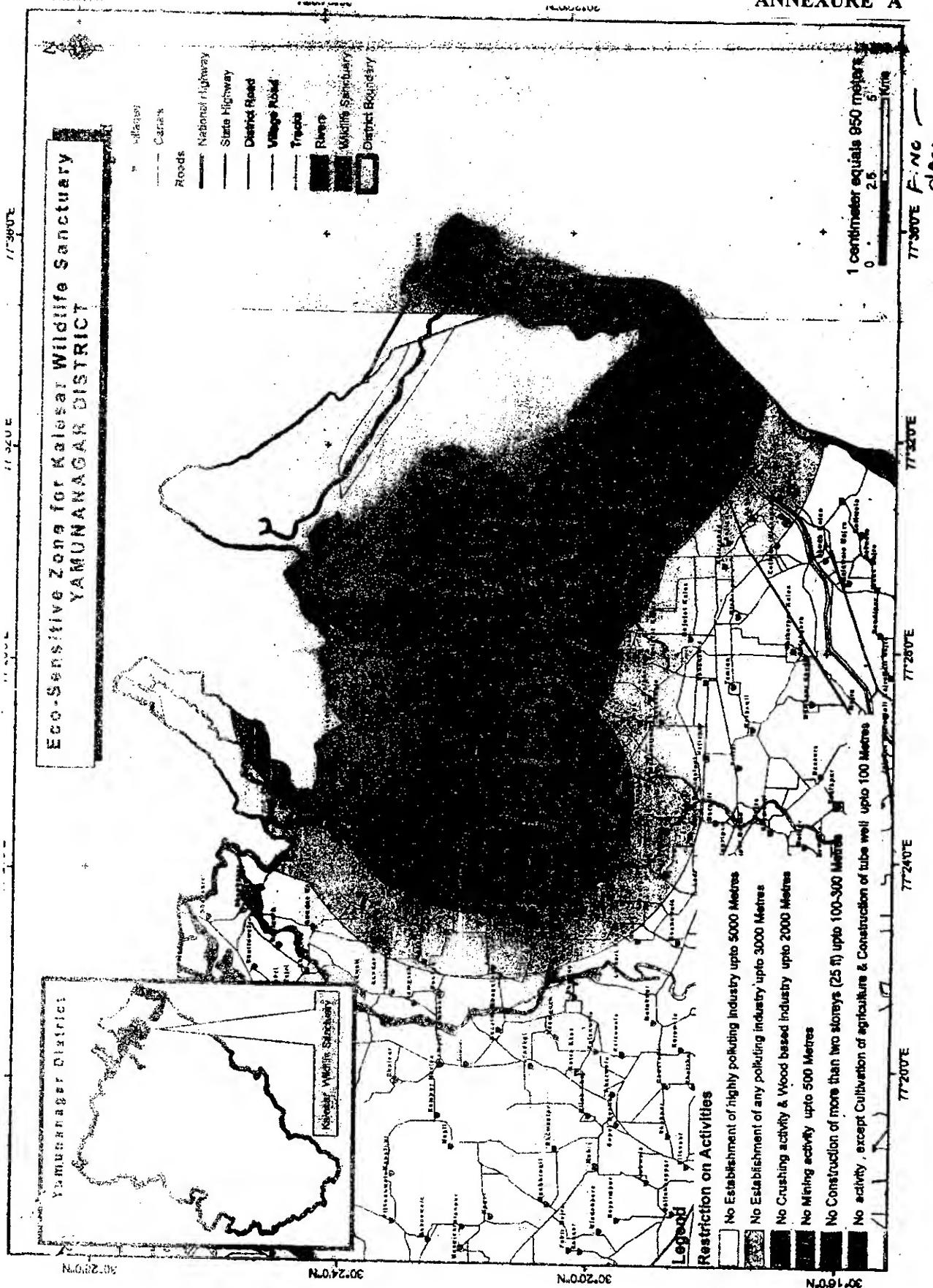
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1394(अ).— खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण शिवालिक पहाड़ी शृंखला पर अवस्थित है जो, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण के बहुत निकट है और दोनों के बीच हवाई दूरी लगभग तीन किलोमीटर है खोल ही रैतान में खड़ी, ढलवा पहाड़ियां हैं और इस अभ्यारण की मिट्टी भी बालुई है तथा अत्यधिक लौह मात्रा के कारण लाल रंग की है ;

और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण महत्वपूर्ण स्थान है और अपने जीव जन्तुओं के कारण जाना जाता है, तेंदुआ, सर्वोच्च क्रम में है, अन्य पशु चीतल या चित्तीदार मृग, सांभर, जंगली सूअर, लघु पुच्छ वानर, लंगूर, लकड़बग्धा, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय लोमड़ी, सियार, साही, आदि हैं ;

और खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का परिस्थितीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस त्रैरीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रमुख लिखेन्द्र

प्राकृत प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील ज्ञेन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज्ञेन खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के पंचकुला जिले में $30^{\circ} 40' 00''$ से $29^{\circ} 32' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 53' 00''$ से $77^{\circ} 01' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज्ञेन का मानचित्र उपांध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज्ञेन में खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है : मनकरुला, झंजरुला, मुहम्मदपुर, पटली, धनावास, वजीरपुर, धानी, रमनगर, सिक्खवाला, घरीहरासर, तुगलकपुर, दया बिहार, कलिवास, इकबालपुर, सैदपुर, खंतावास, हमास्पुर, चंदु, ओमनगर, बिन्धेरा, सुलतानपुर, हरसिंहवाली, धानी, गिर्वीगाली धानी, सहाराना बरभीपुर।

(iii) खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपर्योग द्वारा शासित किए जा रहे हैं।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज्ञेन के लिए ज्ञेनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील ज्ञेन के लिए ज्ञेनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) ज्ञेनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विवारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से समिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iii) ज्ञेनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिदर्तित करना तब के सिदाय ज्ञेनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का विलकुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथित करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपर्युक्त करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में निम्नलिखित क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे—अर्थात्—

(क) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पचास भीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अधिक की विमाओं के नलकूप बैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ग) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(घ) व्यनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(ङ) बहिनावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिनाव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिनाव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ब) ठोस अपशिष्ट :-

- (i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथातन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे।
- (ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिग्राहनतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत शैति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर पिछित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भर्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुमति किया जाएगा।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों को अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है।

(2) मानीटरी समिति दस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विद्युत व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य संस्था निम्नलिखित होंगे :—

I. उप दन पालक (वन्यजीव), पंचकुला, सदस्य-सचिव ;

II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य

III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकुला ; सदस्य

V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकारी ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगा।

- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगठनों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाख्यक



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1394(E).—WHEREAS, the Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary is located in Shiwalik hill system which is very near to Bir Shikargah Wildlife Sanctuary and the aerial distance between the two is about three kilometres. Khol Hai Raitan has steep sloping hills and the soil of this Sanctuary is also sandy loam and has red color because of more iron content;

AND WHEREAS, Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary is important and known for its fauna, leopard is on the top of hierarchy, other animals are Cheetal or Spotted Deer, Sambar, Wild Boar, Rhesus Monkey, Langoor, Hyaena, Jungle Cat, Common Mongoose, Indian Fox, Jackal, Porcupine, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary situated in the Panchkula District of Haryana between $30^{\circ} 40' 00''$ to $29^{\circ} 32' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 53' 00''$ to $77^{\circ} 01' 00''$ East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone is as follows:

Mankaula, Jhanjaula, Mohammadpur, Patli, Dhanawas, Wazirpr, Dhani, Ramnagar, Sikhawala, Ghari Harastu, Tughlakpur, Daya Bihar, Kaliawas, Iqbalpur, Saidpur, Khaintawas, Hamarpur, Chandu, Omnagar, Bidhera, Sultanpur, Harsinghwali, Dhani Mirchiwali Dhani, Sadhrana Barmripur.

(iii) All activities in the Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone -

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. The following activities are to be regulated in the Eco-sensitive Zone, namely:-

(a) Construction Activities:- From the boundary of Khol Hi Raitan Wildlife Sanctuary to a distance of fifty meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.

(b) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(c) Water:-

(i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.

(ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(d) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(e) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(f) Solid Wastes:-

(i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee:-

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

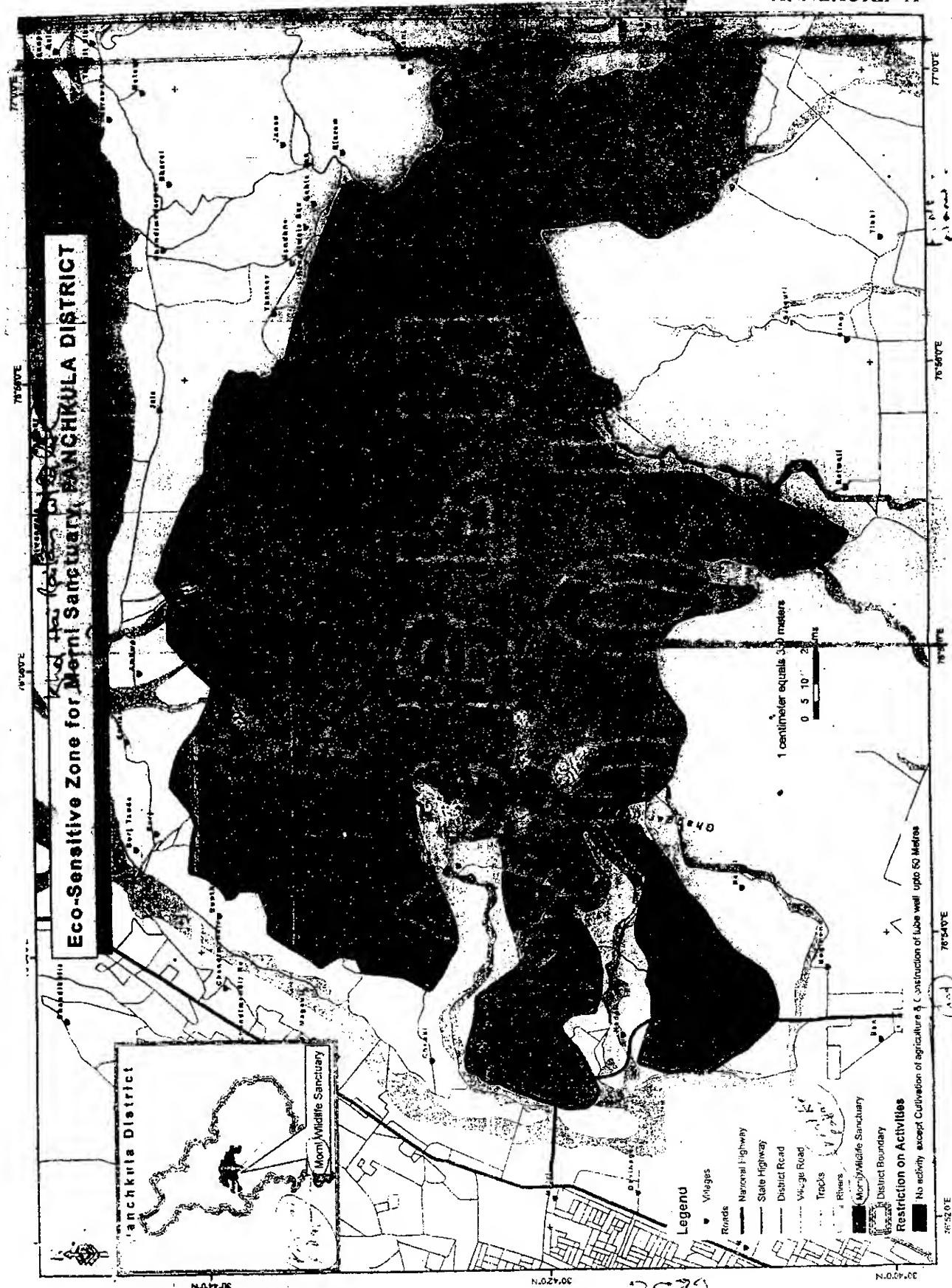
(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

(I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Panchkula as the Member Secretary;

- (II) A representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
 - (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
 - (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Panchkula; Member
 - (V) senior Town Planner of the area; Member
- (3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.
- (4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.
- (5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.
- (7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]
Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1395(अ).—बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला के भीतर आता है और मध्य समुद्र तल से ऊपर लगभग 400 मीटर के अक्षांश पर अन्नस्थित है तथा घागर नदी जलागमों का ऐसा भाग है जो वन क्षेत्रों और कतिपय ग्राम से धिरा हुआ है निकटवर्ती हिमाचल क्षेत्र में उद्गमित कौशल्या नामक एक मौसमी नदी अभ्यारण के बीच से होकर गुजरती है जो वर्षा ऋतु के पश्चात् सूख जाती है और इस अभ्यारण का संपूर्ण क्षेत्र, संगुटिका, चिकनी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी के ढेर की विशिष्टता वाले सिल्ट का बना हुआ है;

और बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण में घना जंगल है और खैर इस क्षेत्र की मुख्य प्रजातियों के रूप में है और यद्यपि इस अभ्यारण का बड़ा भाग प्राकृतिक वन है, किन्तु कई स्थानों पर युक्तिपैट्स और सागौर जैसा प्रजाति वर्ग के मानव द्वारा लगाए गए पौधे हैं तथा जीव जन्तुओं के अतिरिक्त तेंदुआ सर्वोच्च क्रम में है। अन्य पशु चीतल या चित्तीदार मृग, सांभर, जंगली सूअर, लघु पुच्छवानर, लंगूर, लकड़वाघा, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय लोमड़ी, सियार, साही आदि हैं;

और बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली-110003 को लाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: enviseect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के पंचकुला ज़िले में $30^{\circ} 42' 00''$ से $30^{\circ} 50' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 52' 00''$ से $77^{\circ} 03' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है।
 (ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपावंध-क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:
 तापरा, भरूल की सेर, पिंजोर, नालग, कहंगुवाला, सियोरी, रामसर, बटिनान, छटीवाला, धरमपुर, अब्दुल्लापुर, रातपुर, पिंजोर, फिरोजपुर, नानकपुर, देवीलाल, मुगल गार्डन, सूरजपुर, राजीपुर, झजरा, रामपुर, कोटला, भगवानपुर, तोरन, टाड़ां, बुर्जटांडा, बुर्ज, मनधना, पंडितवाला वास, गबलावास, जनसु, जरवरी, सिसराम, भुंड, दंगसना, बटेंगा, भालग, थापली, बल्कु, कदायानी, बरूल, दखरोग, बाधमी, इस्लाम नगर, रायपुर, अम्बाला, थटेर, भराल, मटूर थपली सिक्ख, बलु, जौनपुर, गवाही, खोल, भवाना, भोगपुर, इशामागढ़, नगल, पट्टन, इस्लाम नगर विकन, जला, चंडी मन्दरपुर, नरावल, किदारपुर, धमसु, धयारी, तोरन, भहोरियान, जट्टनवाला, तिब्बील, हरिपुर चफेर खरकुआ, डेरा, दिवानवाला, हरिपुर, अमका, दिवानवाला, जोगीवाला, मल्ला, जबरोट, कजीआना, दथाग्राम, जोधपुर, नंदपुर, भेरगठी, टिल्के, नालाबलोग, नालाधमेर।
 (iii) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के संबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं।
2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

- (i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
 (ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए संबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम रथापनों, वनों के प्रकार और किरम, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, ढागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का स्मीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चयं हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपर्युक्त करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए समिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के संबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

- (I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (III) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

- (I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की तिमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

- (I) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (II) बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (घ) दृश्य :- वन और राजस्व भूमि पर दृश्यों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(ङ) जल :-

- (i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्मावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
- (च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।
- (छ) बहिक्षावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिक्षाव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिक्षाव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

- (i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपूर्णकरण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव नियन्त्रणीय सामग्री को अधिभानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बानिक सामग्री वग व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर विनिहित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपलब्धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है।

(2) मानीटरी समिति दरा से अनधिक सदस्यों से बिलकर बनेगी और नानी श्री समिति वह अधिक्षम ऐसा विषयात् व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रक्रियाई या प्रशासनिक अनुभव और ज्ञानः मुद्दों की सदाचार हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन पालक (वन्य जीव), पंचकुला, सदस्य-सचिव ;
- II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
- III. पर्यावरण (धरोहर राज्य सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य

- IV. प्रान्तिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकुला ; सदस्य

- V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

(3) मानीटरी समिति की शक्तियाँ और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे।

(4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध निभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती।

(6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

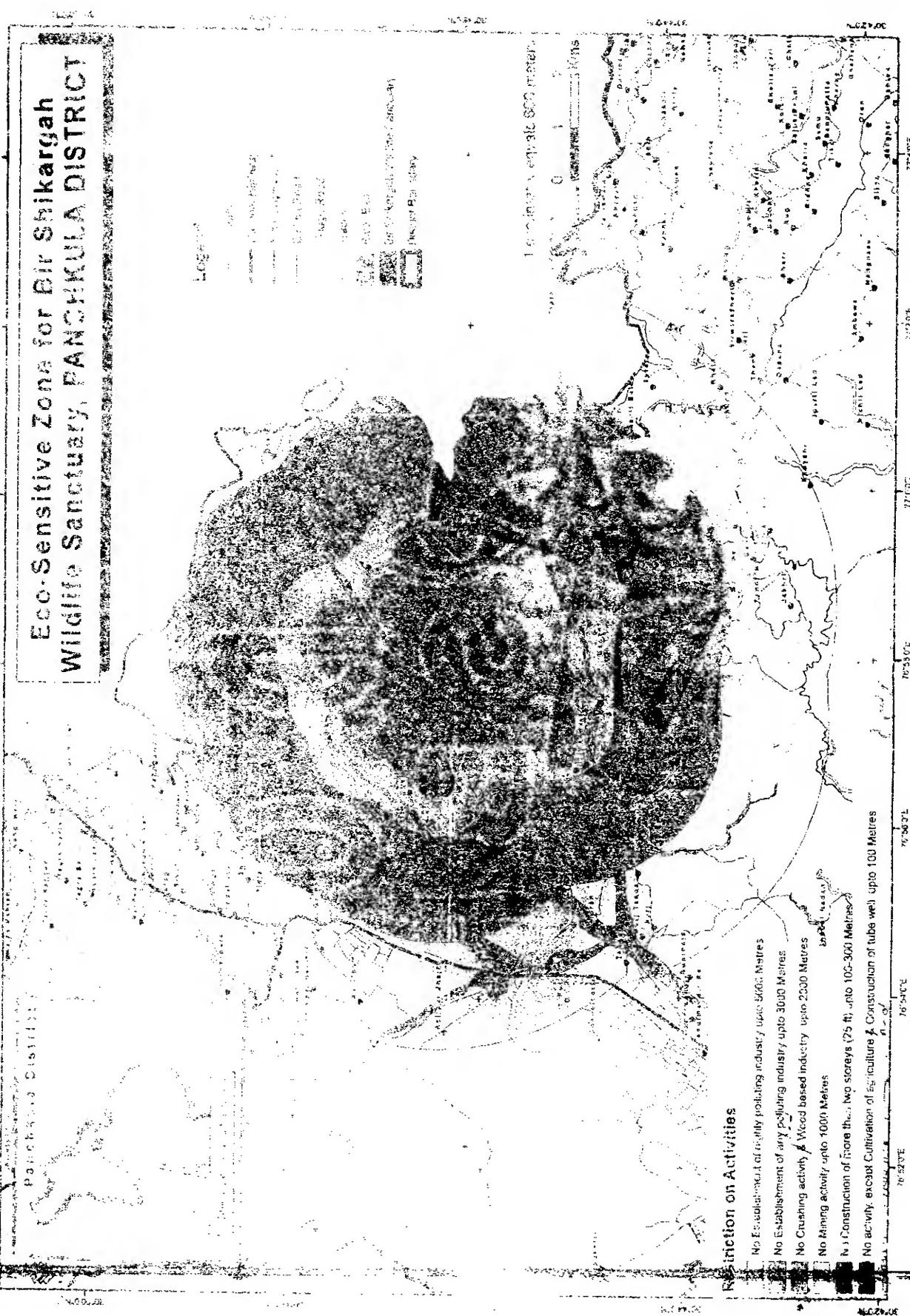
(7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]

डॉ. जी. बी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपर्युक्त

**Eco-Sensitive Zone for Bir Srikargah
Wildlife Sanctuary, PANCHKULA DISTRICT**



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1395(E).—WHEREAS, the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary falls within Shivalik hill system and is located at an altitude of about 400 meter above mean sea level and is a part of Ghaggar river catchments which is surrounded by forest areas and a few villages. A seasonal river named Kaushalya originating in the adjoining Himachal area passes through the sanctuary which goes dry after the rainy season and the entire area of this sanctuary is made up of conglomerates, clay and silt having the characters of alluvial deposits;

AND WHEREAS, Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary has thick forest and Khair as the dominant species of this area and although the larger part of the sanctuary is a natural forest, but at places man made plantations of species like Eucalyptus and Teak have also been grown and besides fauna, leopard is on the top of hierarchy, other animals are Cheetal or Spotted Deer, Sambar, Wild Boar, Rhesus Monkey, Langoor, Hyaena, Jungle Cat, Common Mongoose, Indian Fox, Jackal, Porcupine, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Birshikargarh Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Parivarayan Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:—

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary situated in the Panchkula District of

Haryana between $30^{\circ} 42' 00''$ to $30^{\circ} 50' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 52' 00''$ to $77^{\circ} 03' 00''$ East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Bir Shikargah Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Tapra, Bharun Ki Ser, Pinjore, Nalag, Kahnguwala, Siyori, Ramsar, Batinan, Ghatiwala, Dhatmpur, Abdullapur, Ratpur, Pinjore, Firozpur, Nanakpur, Devilal, Mughal Garden, Surajpur, Rajipur Jhajra, Rampur, Kotla, Bhagwanpur, Toran, Tanda, Burj Tanda, Burj, Mandhana, Panditwala Bas, Gabla Bas, Jansu, Jakhri, Sisram, Bhund, Dangrana, Batera, Bhalag, Thapli Balku, Kadyani, Brun, Dakhrog, Baghami, Islamnagar, Raipur, Ambwala, Thather, Bharal, Mataur, Thapli Sikh, Balu, Jaunpur, Gawahi, Khol, Bhawana, Bhogpur, Ishamagar, Nagal, Pattan, Islamnagar, Chikan, Jala, Chandimandarpur, Narawal, Kidarpur, Dhamsu, Dhayari, Toran, Bahoriyan, Jattanwala Tibbil, Haripurchapher, Kharkua, Dera, Diwanwala, Hanipur, Amka, Diwanwala, Jogiwala, Malla, Jabrot, Kajiana, Dathagram, Jodhpur, Nandpur, Bergati, Tibbe, Nalaballog, Naladhamer.

(iii) All activities in the Bir Shikargah Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.

- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.
- (III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary, construction of any building more than two storey (twenty five ft) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- (I) Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.
- (II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bir Shikargarh Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) **Noise pollution:-** The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) **Discharge of effluents:-** No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) **Solid Wastes:-**

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Panchkula as the Member Secretary;
- (II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Panchkula; Member
- (V) senior Town Planner of the area; Member

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

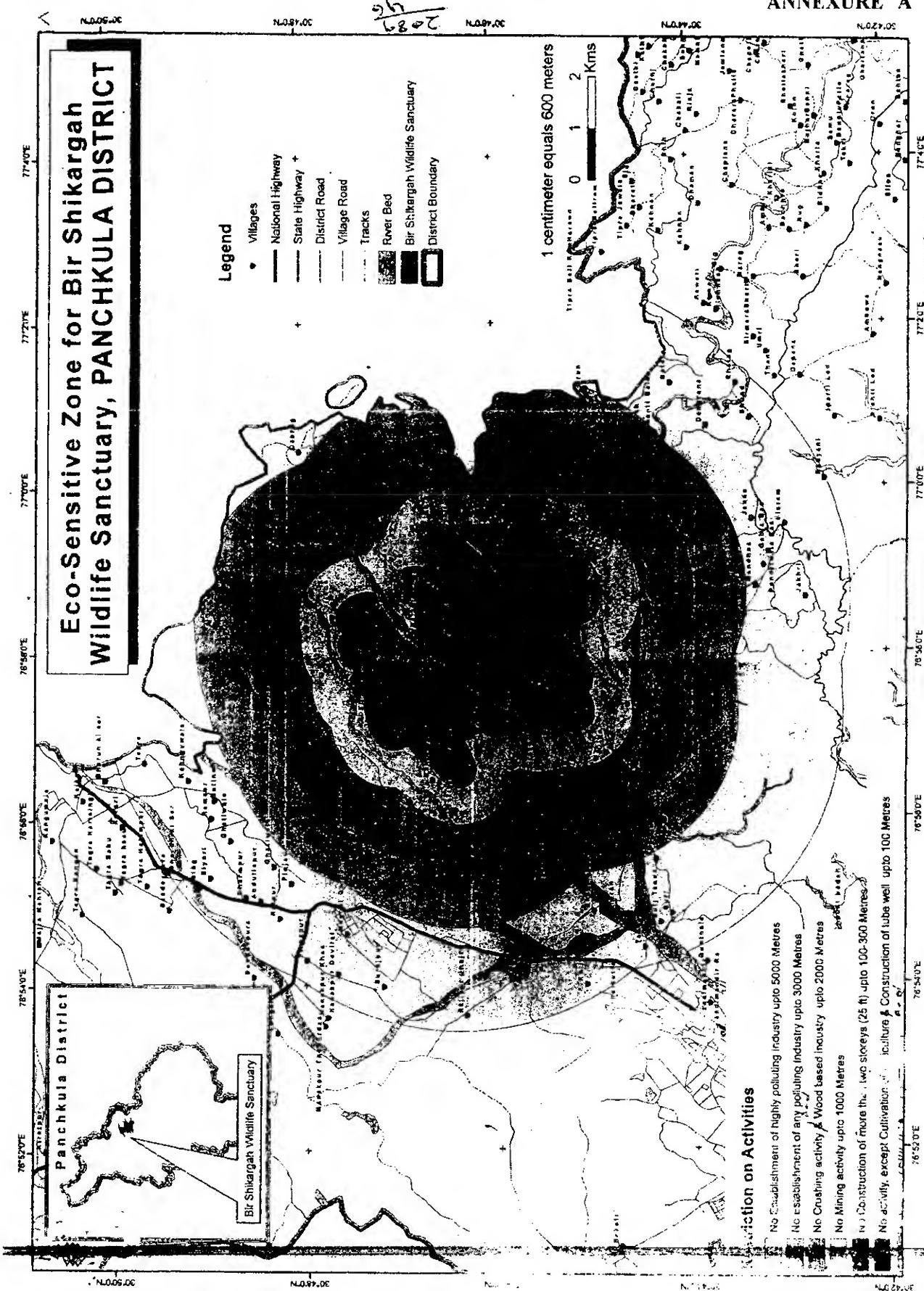
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7). The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment & Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/I/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1396(अ).— नहार वन्य जीव अभ्यारण एक आरक्षित वन है और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है तथा इस क्षेत्र में काला हिस्स, सियार, लोमड़ी, गिरगिट तथा ऐसे ही अन्य छोटे पशुओं की अच्छी आबादी है ;

और नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम¹ (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन नहार वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में $28^{\circ} 20' 00''$ से $28^{\circ} 28' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 21' 00''$ से $76^{\circ} 29' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है ।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानविक्र उपाबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमाओं के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

लिलोध, मुमताजपुर(झलेश), भरंगी, लुखी, गुजरवास, झरोडा, लुलाह अहीर, श्यामनगर (लुलाह जाट), नथेश, कोसली, भकली, घनिया, जीतपास, सुधराना, कोहरार, नेहरुगढ़ (गमरी), सुरहली, नहार, सदातनगर जुदी, झाल ।

(iii) नहार वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विवारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत क्षेत्रों के पुनरथोपन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किसी, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथित करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक रांदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपर्युक्त करेगा और अनुबंधों को अधिकारित करेगा ।

(v) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vi) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) नहार वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में वे मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच सौ मीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

(अ) जल :-

- (i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्गावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
- (च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।
- (छ) बहिस्थायों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्थाव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्थाव जल (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

- (i) ठोस अपशिष्ट के ल्यान का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और रसानीय प्राधिकारी जैव निमीकरणीय और अजैव निमीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपूर्णकरण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।
- (ii) जेत निमीकरणीय सामग्री छो अधिमानसः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनर्व्यक्ति किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्यावरण किसी पर्यावरणीय स्त्रीकृत शीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर नियन्त्रित किए गए रशल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भर्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

- (1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।
- (2) मानीटरी समिति दस से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विष्यात व्यक्ति होगा जिसको रिहृ प्रवंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और रसानीय गुद्यों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

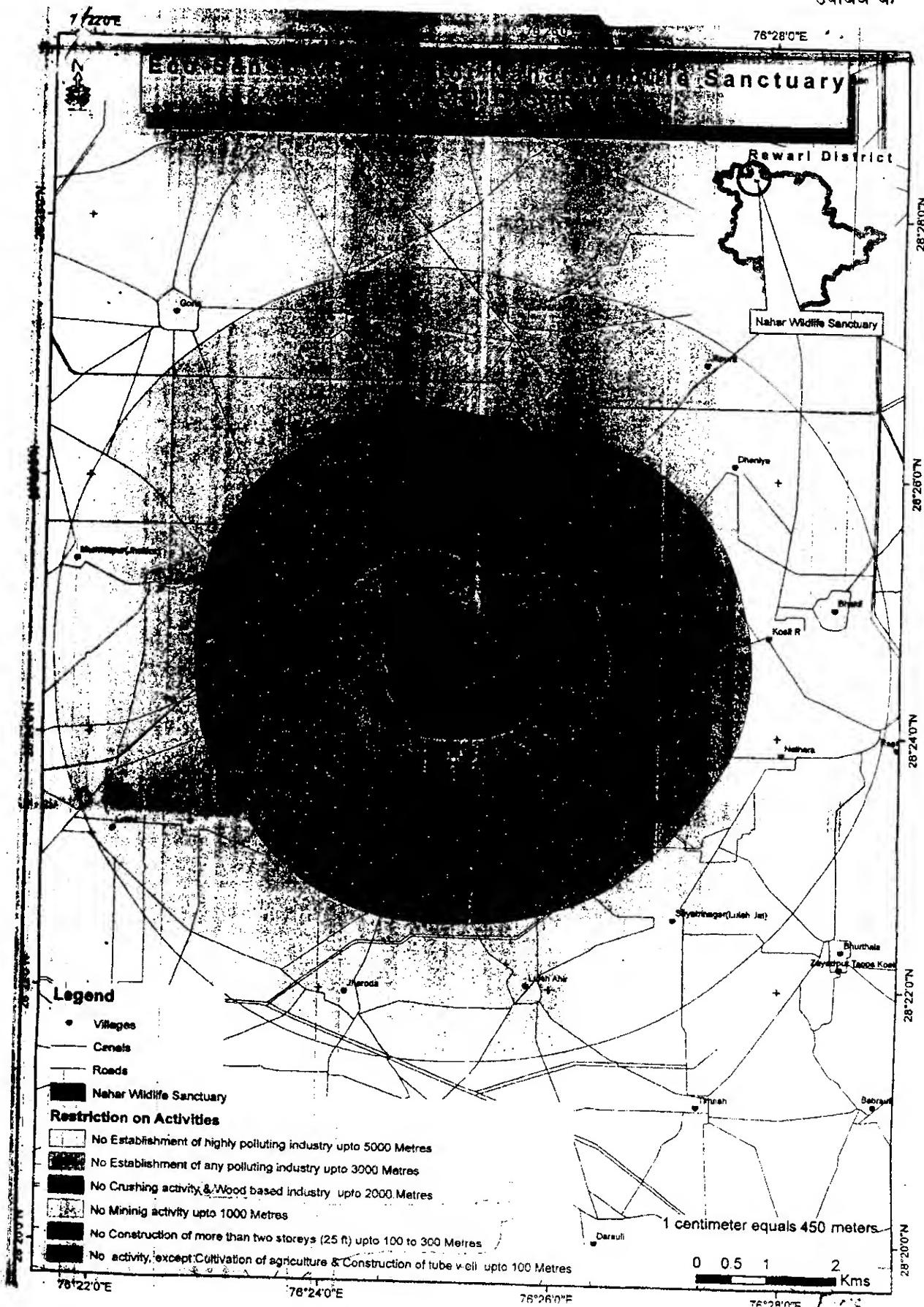
I. उप दग पालक (वन्य जीव), रेताली, सदरग-सचिव ;

- II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
- III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; ; सदस्य
- IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुडगांव ; सदस्य
- V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य

- (3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आक्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होंगा।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपार्थ क



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1396(E).— WHEREAS, the Nahar Wildlife Sanctuary is a reserved forest and falls in the Rewari district of Haryana and is a part of 'National Capital Region' and the area supports a good population of Black Bucks, Jackals, Foxes, Monitor Lizards and such other small animals;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Nahar Wildlife Sanctuary situated in the Rewari District of Haryana between $28^{\circ} 20' 00''$ to $28^{\circ} 28' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 21' 00''$ to $76^{\circ} 29' 00''$ East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Lilodh, Mamtaipur (Jhalera), Bharangi, Lukhi, Gujarwas, Jharoda, Lulah Ahir, Shyamnangar (Lulah Jat), Nathera, Kosli, Bhakli, Dhaniya, Jitpra, Sudhrana, Koharar, Nehrugarh (Gamri), Surhali, Nahar, Sadatnagar, Judi, Jhal.

(iii) All activities in the Nahar Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Nahar Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Nahar Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- (I) Mining upto five hundred meters shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.
- (II) Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Kalesar National Park.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Rewari as the Member Secretary;
- (II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Gurgaon; Member
- (V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SLEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

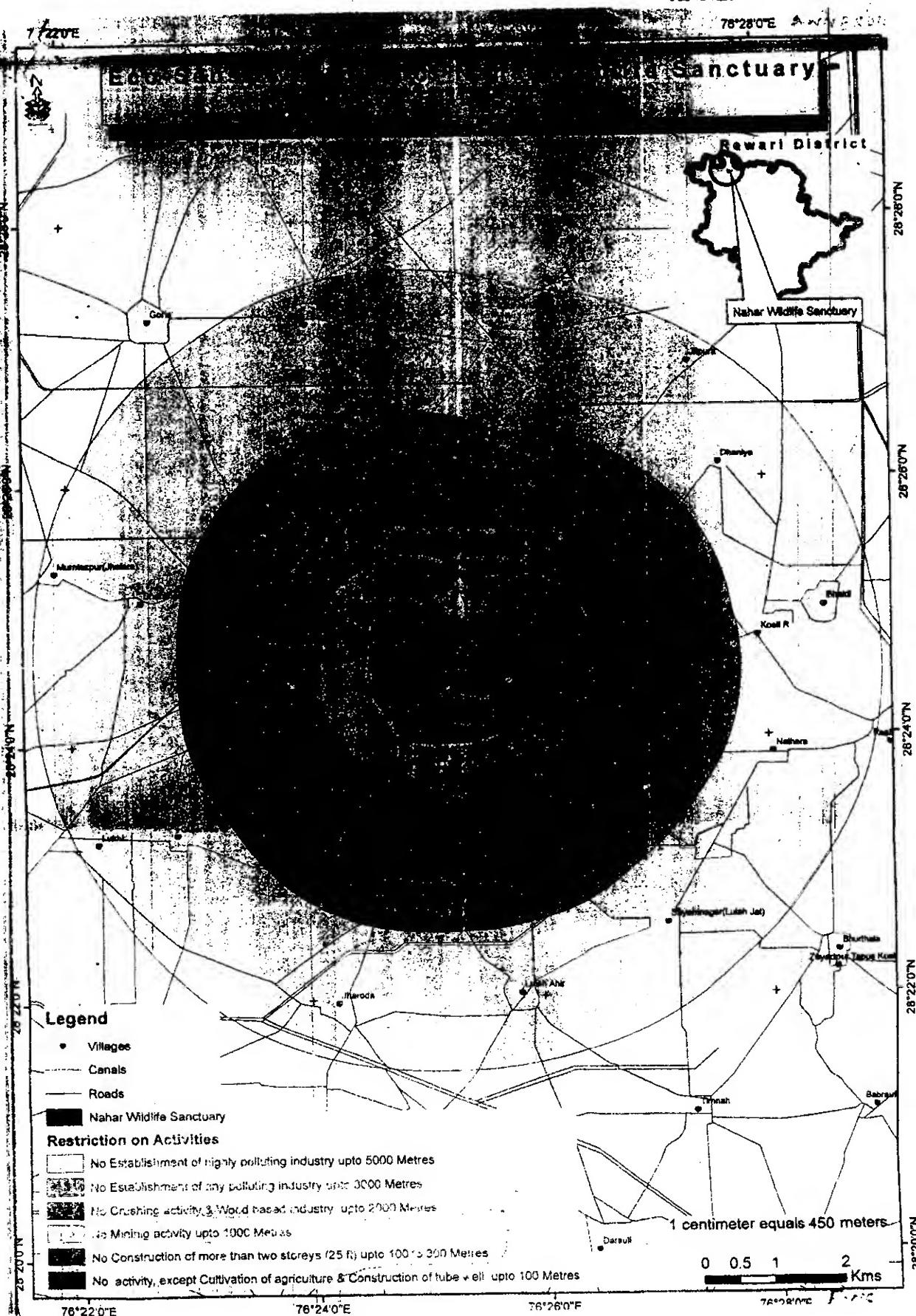
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/3/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'C'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1397(अ).—छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण जो, लगभग 71 एकड़ क्षेत्र में है, एक छोटा सा स्थान है जो, शीतकालीन प्रवारी पक्षियों को आकर्षित करता है और उर्वरक कृषि भूमि से मिल हुआ है;

और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की रीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुख्खा और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (रांगड़ण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे गणित सीमा के भीतर संलग्न छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की रीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (रांगड़ण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसके इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, राठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विवार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विल्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विभिन्न अवधि के भीतर, संघिय, पर्यावरण और जन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, रीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-गेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विवार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन - (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में $29^{\circ} 52' 00''$ से $30^{\circ} 00' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 36' 00''$ से $76^{\circ} 46' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है।

(ii) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

मुर्तजापुर, डेरा, गुरचरन सिंह, छिलोन, नानकपुरा, रुवान, सलेमपुर मदीद, घरासी, कमोदा, लुहार माजरा, रोनानिन्द्रेखारी, मुजीमपुर, रामपुरा, झिवारांवली, गढ़ी, तिकोरां, धिपसारी, रामपुर खेरा, खिजापुरा, साइदान, भोर, सरसा, पिंदासी, सिंहपुरा, गढ़ी सिंघावली, ऐसई माजरा ।

(iii) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समर्चित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से समिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

- (vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी।
- (vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्दिष्ट क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

- (I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (III) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

- (I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से रौ मीटर की दूरी तक एक हजार धन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप वैंकर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो गंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) उत्खनन और खनन :-

- (I) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (II) छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर तृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(क) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।

(छ) बहिस्त्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्त्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्त्राव जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथातन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिह्नित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

4. मानीटरी समिति-

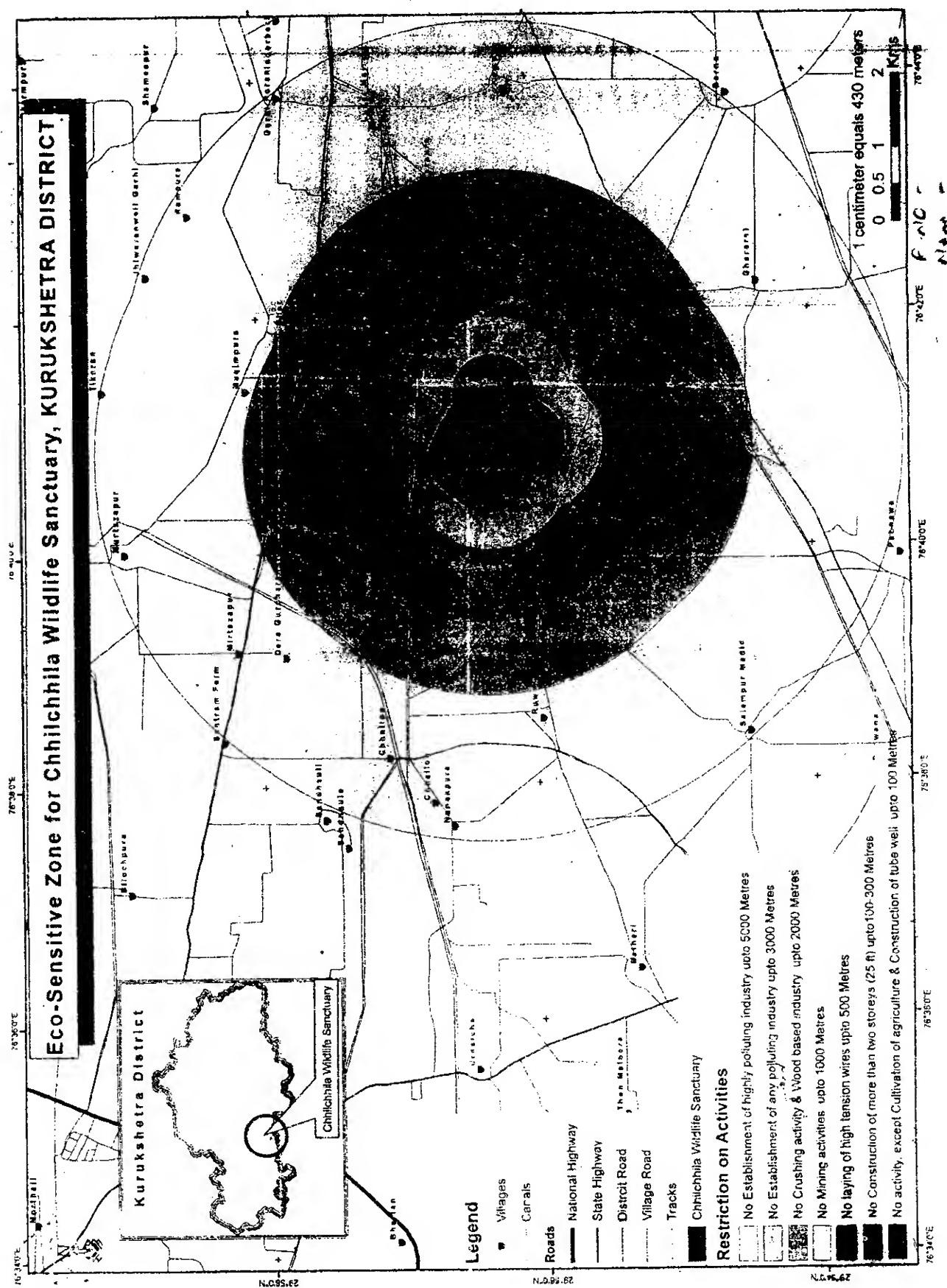
(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विद्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन पालक (वन्य जीव), कुरुक्षेत्र, सदस्य-सचिव ;
 - II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
 - III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य
 - IV. प्राकेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ; सदस्य
 - V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियाँ और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्णीत होंगी ।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिभूदना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर भुद्धा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी ।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्णय के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008 ईएसजे८]
डॉ. जी. वी. मुद्रमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध क



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1397(E). WHEREAS, the Chhilchhila Wildlife Sanctuary which is about 71 acres in area, is a small depression which attracts winter migratory birds and surrounded by fertile agriculture land;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Parivaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi 110003, or electronically at e-mail address: envsectr@nic.in.

DRAFT PROPOSALS**Boundaries of Eco-sensitive Zone:-**

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary situated in the Kurukshetra District of Haryana between $29^{\circ} 52' 00''$ to $30^{\circ} 00' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 36' 00''$ to $76^{\circ} 46' 00''$ East longitude:

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary in the Eco sensitive Zone are as follows:

Murtazapur, Dera Gurcharan Singh, Chhallon, Nanakpura, Kuwan, Salempur Madid, Ghararsi, Kamoda, Luhar Majara, Rotaninderbari, Muzumpur, Rampura, Jhiwaranwah,

Garhi, Tikoran, Dhipsari, Rampur Khera, Khizapura, Saidan, Bhor, Sarsa, Pindarsi, Singhpura, Garhi Sighawali, Bhainsae Majra.

(iii) All activities in the Chhilchhila Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone:-

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.
- (III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Chhilchhila Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five ft) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary.
- II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Chhilchhila Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Kurukshetra as the Member Secretary;
- (II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Yamunanagar; Member
- (V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

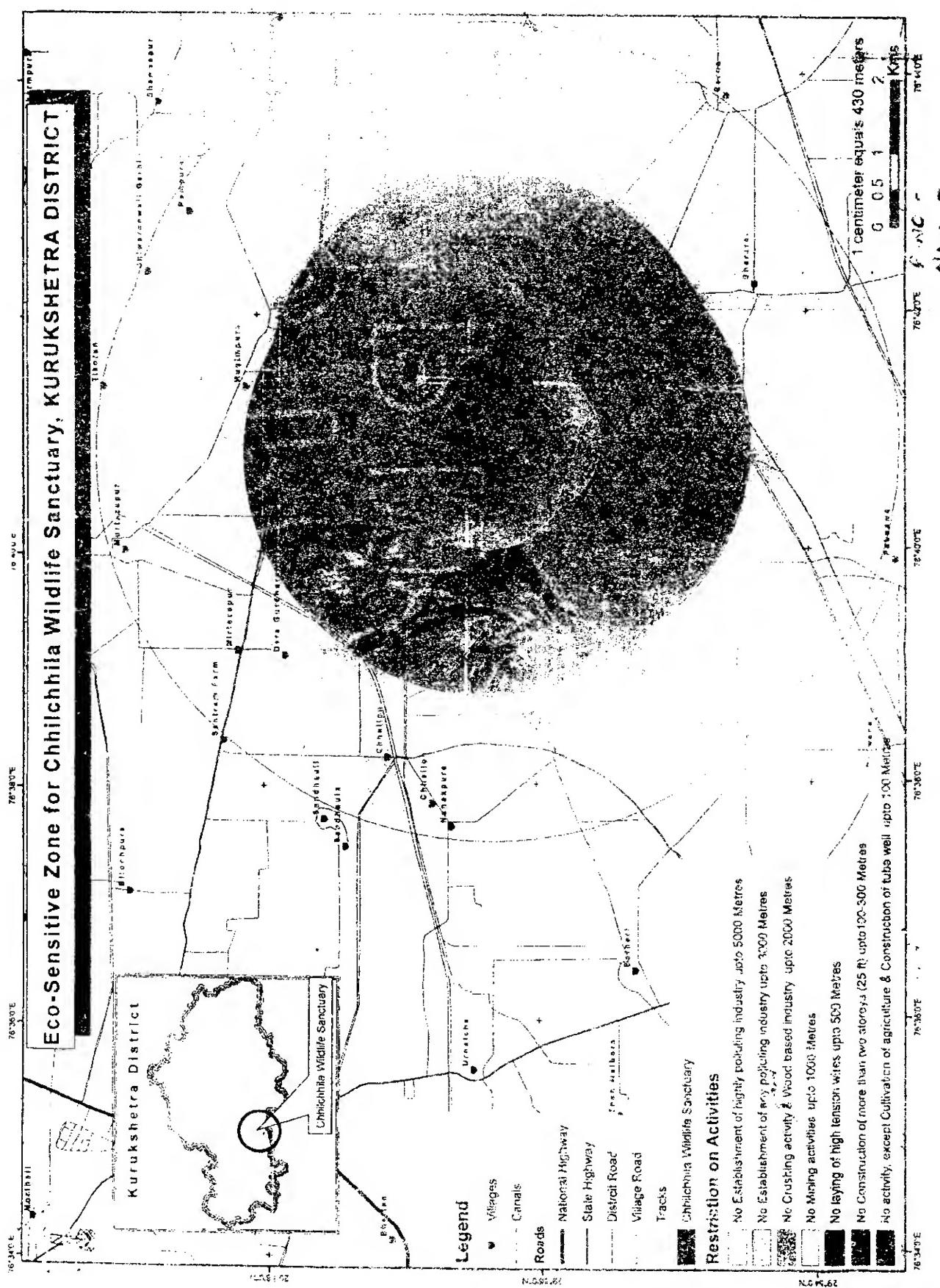
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1398(अ).— अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण किसी विशिष्ट मरुस्थल, पारिस्थितिकीय प्रणाली का प्रतीक है, किन्तु वहाँ ऐसा कोई पौधा नहीं पाया जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हो और यह कारो मृगों के स्वचंद्र निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और मानव क्रियाकलापों की वृद्धि के कारण उनमें से कुछ को भुराक्षित निवास स्थान की ओर में उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है;

और अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुख्ता और संरक्षण करने की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की घारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप प्रस्ताव

- पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन -

(i) एक अद्वितीय संवेदनशील जोन अदुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर के बीच से, उत्तरी दृश्यमान के सिरसा जिले में $29^{\circ} 42' 00''$ से $29^{\circ} 57' 00''$ उत्तरी अक्षांश और 74° 45' 00'' से $74^{\circ} 50' 00''$ दूरी दैरहार ते मध्य में स्थित है।

(ii) एक अद्वितीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपावंश -के पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में शामिल है, जो भौतिक प्रभावों की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

गोविंदगढ़, गैजनड़, शुकाहाट, गुडसर, कलुआना, लौहगढ़, शेरगढ़, लाम्बी, धानी, नानुपुरा, मोहनगढ़, गोविंदगढ़, लखुवाना, गोविंदगढ़।

उत्तरी अदुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (वन्य जीव) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के तहत क्रियाकलाप किए जा रहे हैं।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा उत्तरी अधिसूचना के प्रकाशन एवं तारीख से एक वर्ष और उत्तरी भौतिकी के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भवित्व संशोधन के पर्यायवर्ण और उत्तरी नियमन को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) जोनल मास्टर प्लान तक संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और अपरिव्यवस्था इसमें एवं व्यापारी और पारिस्थितिकीय विवारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कानून का रामबद्ध स्वयं से समन्वित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान विकासों के संखार, जलवायन क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आद्रता संखण, राज्यीय समुदाय को आवाहनकारी तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दें वह आवश्यकता है।

(iii) जोनल मास्टर प्लान की विद्यमान ग्राम स्थापनों, वर्गों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित अवलोकनीय क्षेत्र, बाजारों, दुकानों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे नामान् वास्तवीय क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए तब के लिए ये जोनल भास्तर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। वह कृषि भूमि जो एक विलुप्त रूपमें संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान अव्यापी नियन्त्रित की आवश्यकीय अवलोकनकारों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iv) जोनल मास्टर प्लान ने उत्तरी भौतिकीय समीक्षा के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु उत्तरी भौतिकीय नियन्त्रित कानून का नियन्त्रित किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपर्दर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयाँ :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) अबुबशहर वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदर्भन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(स) दृष्टि :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामनिश्चित किसी प्राप्तिकारी द्वारा अनुमतिप्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(ड) जल :-

(i) भूपैयत जल का नियन्त्रण केवल राजभावपूर्वक कृषि और धरेनु खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्ण अनुदोषन के सिवाय, भू-जल का विकास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोपण के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(ब) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय उंवेदनशील जोन में ध्वनि प्रदूषण के लिए मानदंडक नियम और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा।

(छ) बहिकारी का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के अन्तर किसी जल (जल विद्युत अनुपचारित या औद्योगिक बहिकार नियमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बाह्यस्थाव जल (जल विद्युत नथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपर्योग लो पूँज करेंगे।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्यवन द्वा कियावयन नगरालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथात्त) नियम, 2000 के उपर्योग के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव नियोकरणीय और अजैव नियोकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपूर्णकरण के लिए शोषणारेतेयार करेंगे।

(ii) जैव नियोकरणीय सामग्री को कमिसामत खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनर्वाहित किया जाएगा और अकारीनेक सामग्री को लाइन फिल्टर पर्यावरणीय स्वीकृत शैलि से पारिस्थितिकीय राषेकनशील जोन के बाहर विनियत किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भर्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा।

4. मानीटरी समिति

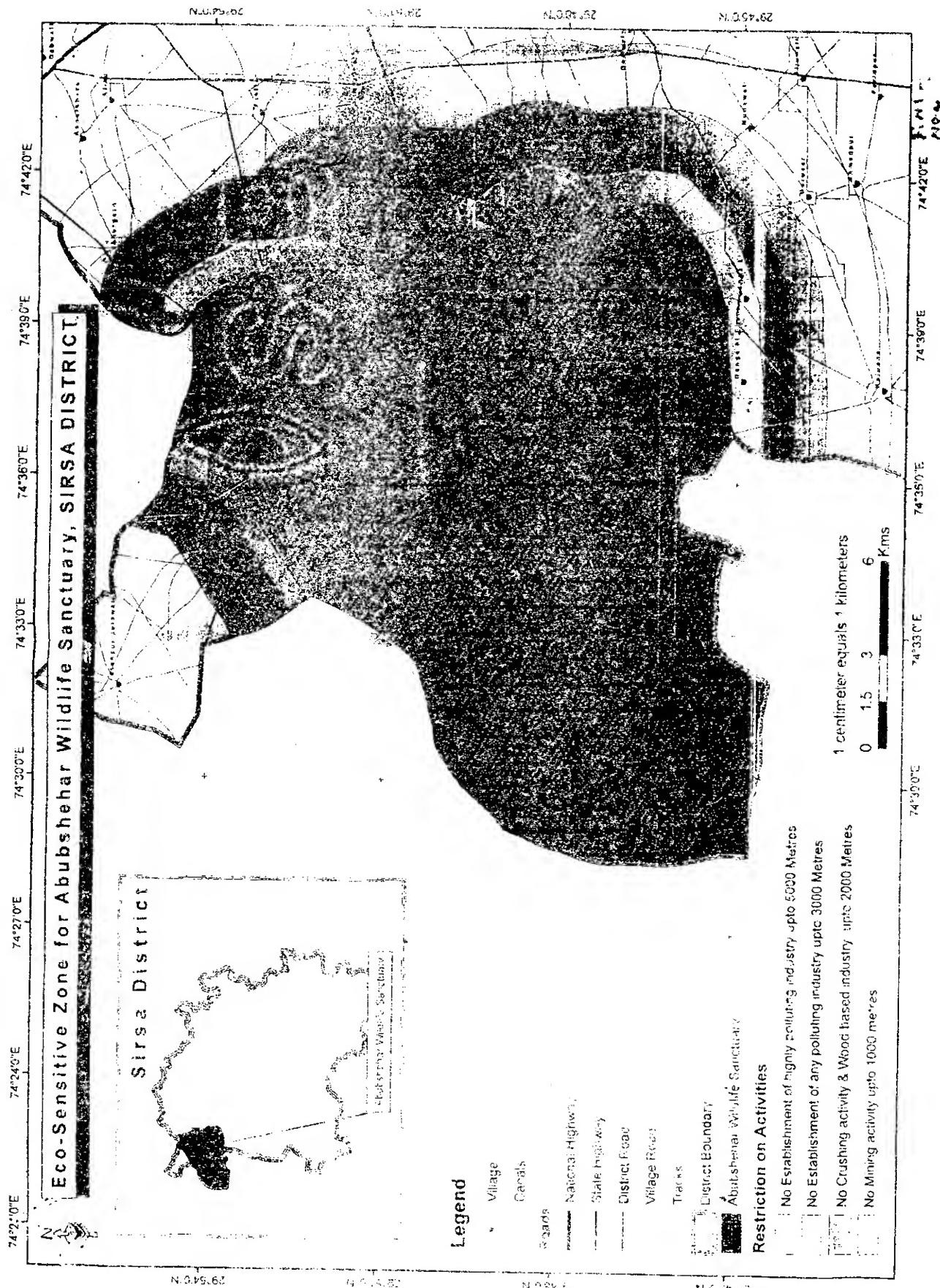
(१) नियन्त्रण नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन इस अधिसूचना के उपर्योग को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है।

(2) मानीटरी समिति दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विद्युत्यात् व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन पालक (वन्य जीव), सिरसा, सदस्य-सचिव ;
 - II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
 - III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य
 - IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार, सदस्य
 - V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्दिष्ट होंगे।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 गार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपायक



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1398(E).— WHEREAS, the Abubshaher Wildlife Sanctuary represents a typical desert ecosystem, but there is no plant found here which is endemic to this area and is known for its open habitat of Black Bucks and due to increasing human activities may force some of them leave the area in search of safer habitat;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. **Boundaries of Eco-sensitive Zone:-**

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary situated in Sirsa District of Haryana between $29^{\circ} 42' 00''$ to $29^{\circ} 57' 00''$ North latitude and between $74^{\circ} 27' 00''$ to $74^{\circ} 45' 00''$ East longitude.

(ii) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Masitan, Maujgarh, Munawall, Garusar, Kaluana, Lohgarh, Shergarh, Lambi, Dhani Nanupura, Modi, Govindgarh, Lakhwana, Ganga Dhani.

(iii) All activities in the Abubshaher Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

- (I) No wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Abubshaher Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary.
- II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Abubshaher Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Sirsa as the Member Secretary;
- (II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Hisar; Member
- (V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority, which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

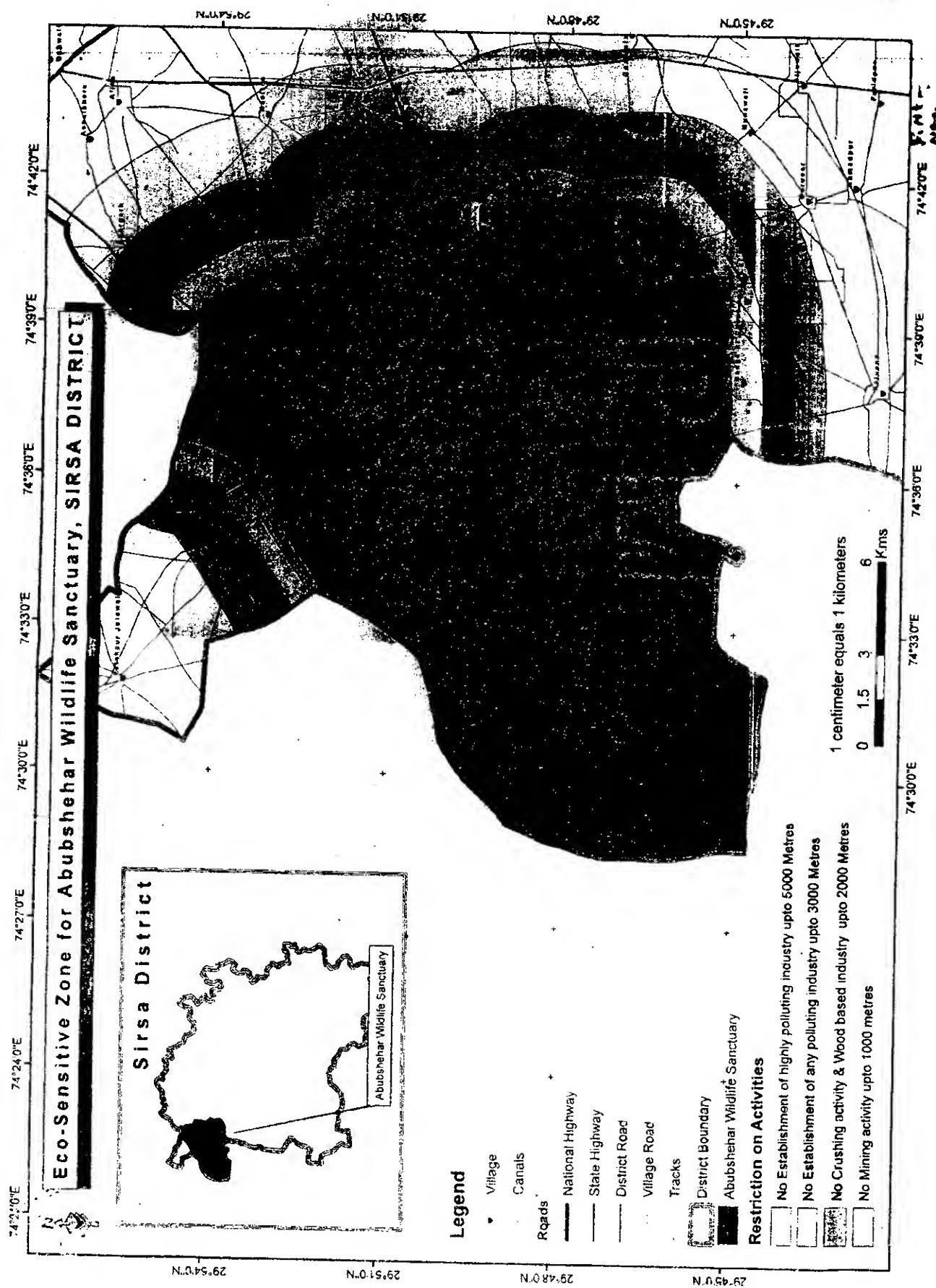
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1399(अ).—भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण (दिल्ली के पश्चिम से लगभग 80 किमी.) शीतकाल तथा राजस्थान के भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में जल समस्या के दौरान 250 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की लगभग 35000 किस्मों को आकर्षित करता है और यह अभ्यारण प्रवासी जल मुर्मियों के लिए वैकल्पिक शीतकालीन स्थल उपलब्ध करवाता है जिसके कारण इसका महत्व बढ़ गया है ;

और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को लाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन -

- (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के झज्जर जिले में $28^{\circ} 28' 00''$ से $28^{\circ} 36' 00''$ उत्तरी अक्षांश और 76°

28° 00" से 76° 38' 00" पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र उपांबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में बिंडवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

आजादनगर, खपरवास, बहालगढ़, बम्बुलिया, मुंडाहरा, खुंडेराली, निलाहेरी, चंदौल, धाकला, कासनी, हसनपुर, जवाहरनगर, कर्णेधा, सूरजगढ़, कोयलपुरी, कौंजीया, खेतावास, फतेहपुरी, बिंडवास, शहाजहांपुर कनावाह, नवादा, रेखुवास, चधवाना, बिलोचपुर ।

(ii) बिंडवास वन्य जीव अभ्यारण के सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान सभी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरिया ॥ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्यक् रूप से सम्मिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत्त क्षेत्रों के पुनर्रूपन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और गढ़ता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिल्कुल सीमित संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य स्तरीय मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

(vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई परिणामिक कमी नहीं होगी ।

(vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी ।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप-

(क) औद्योगिक इकाइयां :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(III) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अधिक की विमाओं के नलकूप वैंडर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ग) उत्खनन और खनन :-

(I) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(II) भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदलन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(घ) वृक्ष :- वन और राजस्व भूमि पर वृक्षों की कटाई सरकार या उस प्रयोजन के लिए नामिकिटिंग किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रबंध योजना के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(ङ) जल :-

(i) भूमिगत जल का निष्कर्षण केवल सद्भावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग हंरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा।

(छ) बहिस्त्रावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपचारित या औद्योगिक बहिस्त्राव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्त्राव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

(i) ठोस अपशिष्ट के व्ययन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे।

(ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृषि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्ययन किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए स्थल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा।

4. मानीटरी समिति-

(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है।

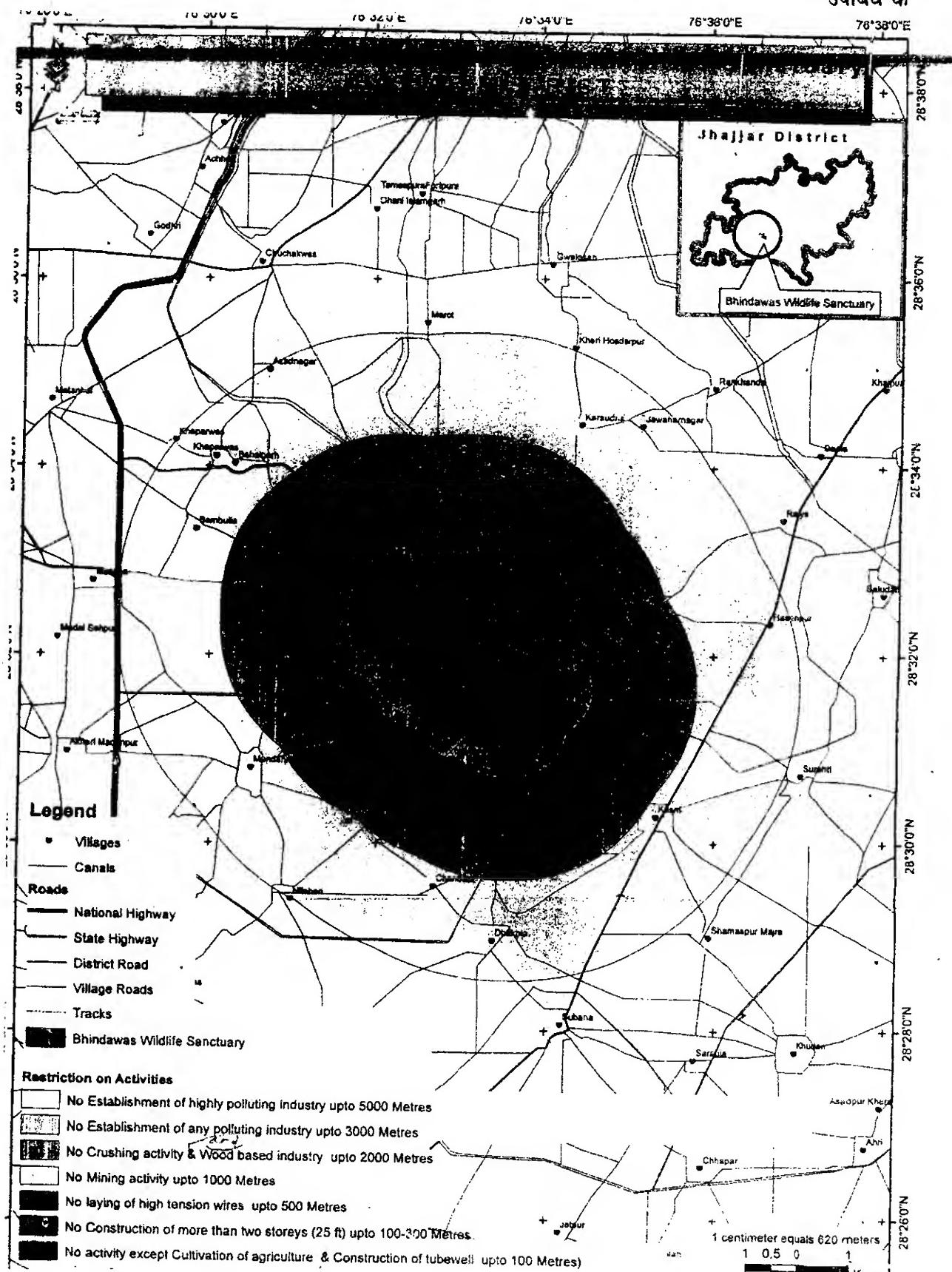
(2) मानीटरी समिति दस से अधिक सदस्यों से गिलफर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विचारात् नामित होता जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन परक (वन्य जीव), झंडार, सदस्य-सचिव ;
- II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
- III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यस्त गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामिटिएट किया जाए ; सदस्य
- IV. प्राकृतिक अधिकारी, हरिगाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहानुगढ़; सदस्य
- V. धोप का ऊर्ध्व नगर योजनाकार ; सदस्य

- (3) मानीटरी समिति की शक्तियाँ और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्विधित होंगे।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्ण अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 रितांबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगमों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अननुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा।

[फा. सं. 30/1/2008-ईसजेड]
डॉ. जी. वी. मुब्रहमन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपांकथं क



NOTIFICATION

Dated 10th June, the 3rd June, 2009

S. I. (3896). WHINDEAS, in Haryana, was Wildlife Sanctuary (about 80 kilometers from West of Delhi) attracts around 3,00,000 numbers of migratory birds belonging to over 250 species during winter and wintering place of Bharatpur National Park of Rajasthan, this Sanctuary provides an alternate wintering route to the migratory water fowls which has enhanced its importance;

AFTER WININGAS, it is proposed to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone (also known as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (iv) and clause (xiv) of sub - section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Parivartan Bhawan, CGO Complex, Lajpat Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisec1@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

i. Boundaries of Eco-sensitive Zone:

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary situated in the Jhajjar District of Haryana between $28^{\circ} 28' 00''$ to $28^{\circ} 36' 00''$ North Latitude and between $76^{\circ} 28' 00''$ to $76^{\circ} 38' 00''$ East Longitude and the map of the Eco-sensitive Zone is in Annexure-A and the list of the villages lying within five kilometers distance of the boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Chhajjar, Khaparwali, Dholiwal, Banjoli, Bhundal, Khundherali, Nitaher, Chandauli, Pura, Kasni, Mihir, Deobiragar, Karoli, Kuragadi, Koyalpuri, Kamjhish, Udeawas, Patehpur, Chhawas, Shobhanpur, Kawali, Nawada, Redhwas, Chadhwana, Balochpur.

(ii) All activities in the Bhindawas Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and approved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

- (I) No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.
- (II) No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(III) No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- (I) From the boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- (II) In the area falling between one hundred meters to three hundred metets from the boundary of Bhindawas Wildlife Sanctuary, new construction of any building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary.
- II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Bhindawas Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee:-

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- (I) Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Jhajjar as the Member Secretary;
- (II) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- (III) one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- (IV) Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Bahadurgarh; Member
- (V) senior Town Planner of the area; Member.

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

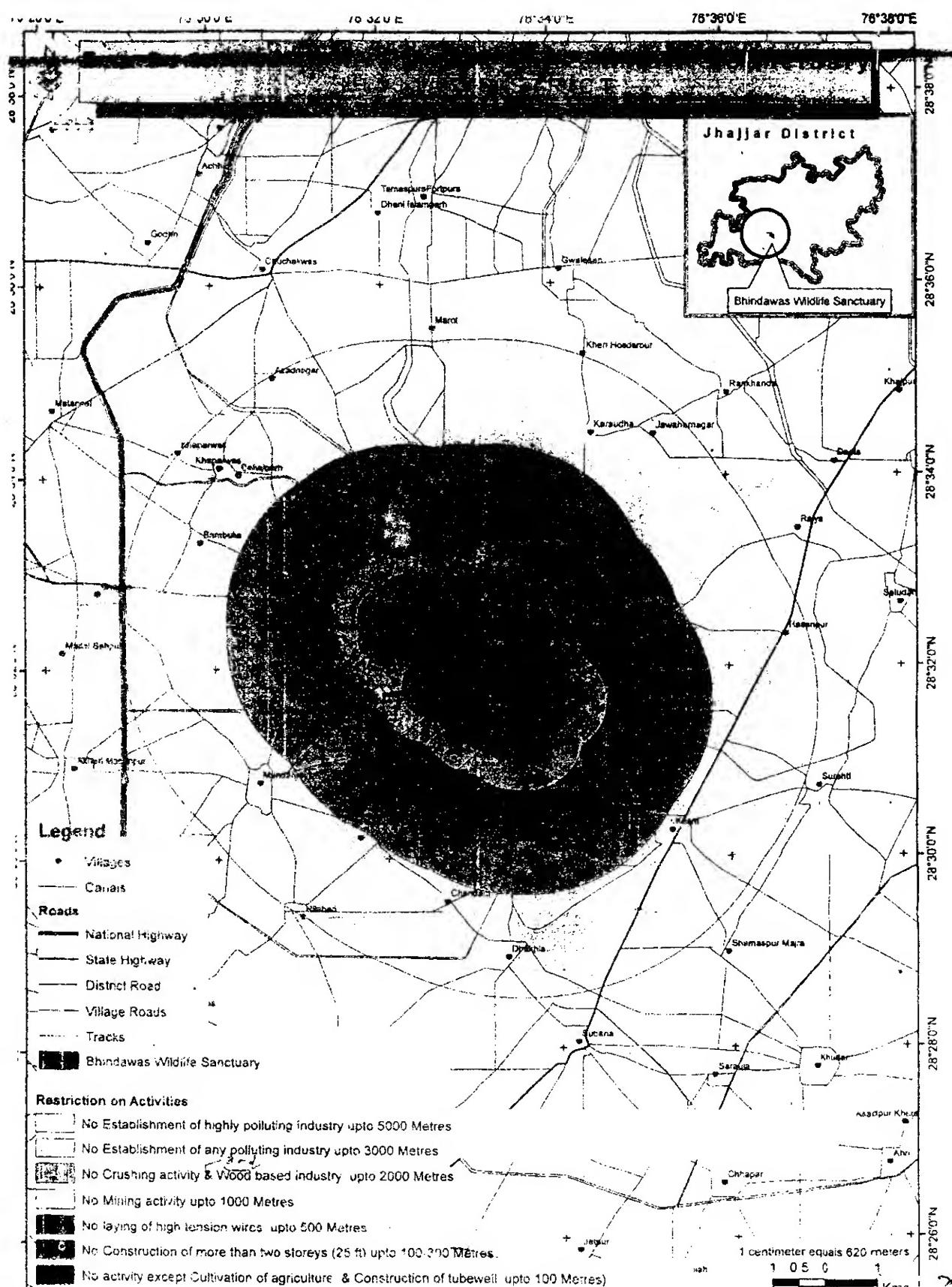
(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A



अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2009

का.आ. 1400(अ).—खपरवास वन्य जीव अभ्यारण (दिल्ली के पश्चिम से लगभग 80 किमी.) बड़ी संख्या में और अनेक किलोमीटरों के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और यह मिठावास वन्य जीव अभ्यारण से लगभग 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है ;

और खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र का पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन के रूप में सुरक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य में नीचे वर्णित सीमा के भीतर संलग्न खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘पर्यावरणीय संवेदनशील जोन’ (जिसमें इसके पश्चात् पर्यावरणीय संवेदनशील जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध कर दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् दिवार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता: envisect@nic.in पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसा कर सकेगा ।

प्रारूप प्रस्ताव

1. पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन -

- (i) उक्त पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र है, जो हरियाणा के झज्जर जिले में $28^{\circ} 30' 00''$ से $28^{\circ} 38' 00''$ उत्तरी अक्षांश और $76^{\circ} 28' 00''$ से $76^{\circ} 38' 00''$ पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन का मानचित्र

उपबंध -क पर है और पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :

छुछकवास, भरोट, खेरी होसदासपुर, करौथा, शहजाहांपुर, चधवाना, रेहुवास, मुंडास, धानी इरलामगढ़, आजादनगर, खपरवास, बहालगढ़, बम्बुलिया, खेतावास, कोयलपुरी, विलोचपुर, भिंडवास, सूरजगढ़, नवादा ।

(ii) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के रामी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित किए जा रहे हैं ।

2. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर-

(i) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) जोनल मास्टर प्लान रामी संबद्ध राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगरपालिका और राजस्व विभाग तथा इसके पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समन्वित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को साध्यक् रूप से समिलित करके तैयार किया जाएगा तथा निरावृत क्षेत्रों के पुनर्स्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलागम क्षेत्रों के प्रबंध, जल भरण प्रबंध, भूमिगत जल प्रबंध, मृदा और आदला संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं के लिए उपबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(iii) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान ग्राम स्थापनों, वनों के प्रकार और किस्म, कृषि क्षेत्र, उर्वरक भूमि, हरित क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र, बागानों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगा और हरित उपयोग से भूमि के उपयोग में जैसे बागान, बागवानी क्षेत्र, कृषि उद्यान और ऐसे ही अन्य स्थानों को गैर हरित उपयोग के लिए परिवर्तित करना तब के सिवाय जोनल मास्टर प्लान में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब कृषि भूमियों का बिलकुल रीमिट संपरिवर्तन विद्यमान स्थानीय जनसंख्या के प्राकृतिक विकास के साथ विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो ।

(iv) जोनल मास्टर प्लान राज्य रसायन मानीटरी समिति के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले किसी विनिश्चय हेतु जिसके अंतर्गत शिथिल करने के लिए विचार किया जाना भी है, एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

(v) जोनल मास्टर प्लान, यातायात के विनियमन के लिए उपाय उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा ।

- (vi) पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान की तैयारी के लंबित रहने और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसका अनुमोदन सभी नए संनिर्माण प्रस्तावों की संवीक्षा किए जाने और पैरा चार में यथानिर्दिष्ट मानीटरी संगिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा और वन, हरित और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कमी नहीं होगी।
- (vii) राज्य सरकार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि आवश्यक हों, विहित करेगी।

3. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में विनियमित या निर्बंधित क्रियाकलाप:

(क) औद्योगिक इकाइयां :—

- (I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से तीन किलोमीटर के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।
- (III) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर किसी नए उच्च प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

(ख) संनिर्माण क्रियाकलाप :—

- (I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर की दूरी तक एक हजार घन इंच से अनधिक की विमाओं के नलकूप चैंबर के सिवाय, किसी प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से सौ मीटर से तीन सौ मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिला (पच्चीस फीट) से अधिक किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (III) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से पांच सौ मीटर की दूरी तक नई उच्च दाब वाली पारेषण तार का विछाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) उत्खनन और खनन :—

- (I) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक खनन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (II) खपरवास वन्य जीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दो किलोमीटर तक संदर्भान्वयन कार्य अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ङ) जल :-

- (i) भूमिगत जल का निर्कर्षण केवल सद्मावपूर्वक कृषि और घरेलू खपत के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिद्धांश, भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिशके अंतर्गत कृषि से संदूषण और प्रदूषण भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
- (च) ध्वनि प्रदूषण :- पर्यावरण विभाग या राज्य वस विभाग हरियाणा पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में ध्वनि प्रदूषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम बनाने वाला प्राधिकारी होगा ।
- (छ) बहिस्थावों का निर्वहन :- पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के भीतर किसी जल निकाय में कोई अनुपवारित या अधिकारिक बहिस्थाव निर्गमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उपचारित बहिस्थाव जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों को पूरा करेंगे ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :-

- (i) ठोस अपशिष्ट के व्यवन का क्रियान्वयन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संप्रकरण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ।
- (ii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या धूमि स्त्रेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का व्यवन किरणी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के बाहर चिन्हित किए गए रथल पर किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्टों का जलाना या भस्मीकरण पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन में अनुज्ञात किया जाएगा ।

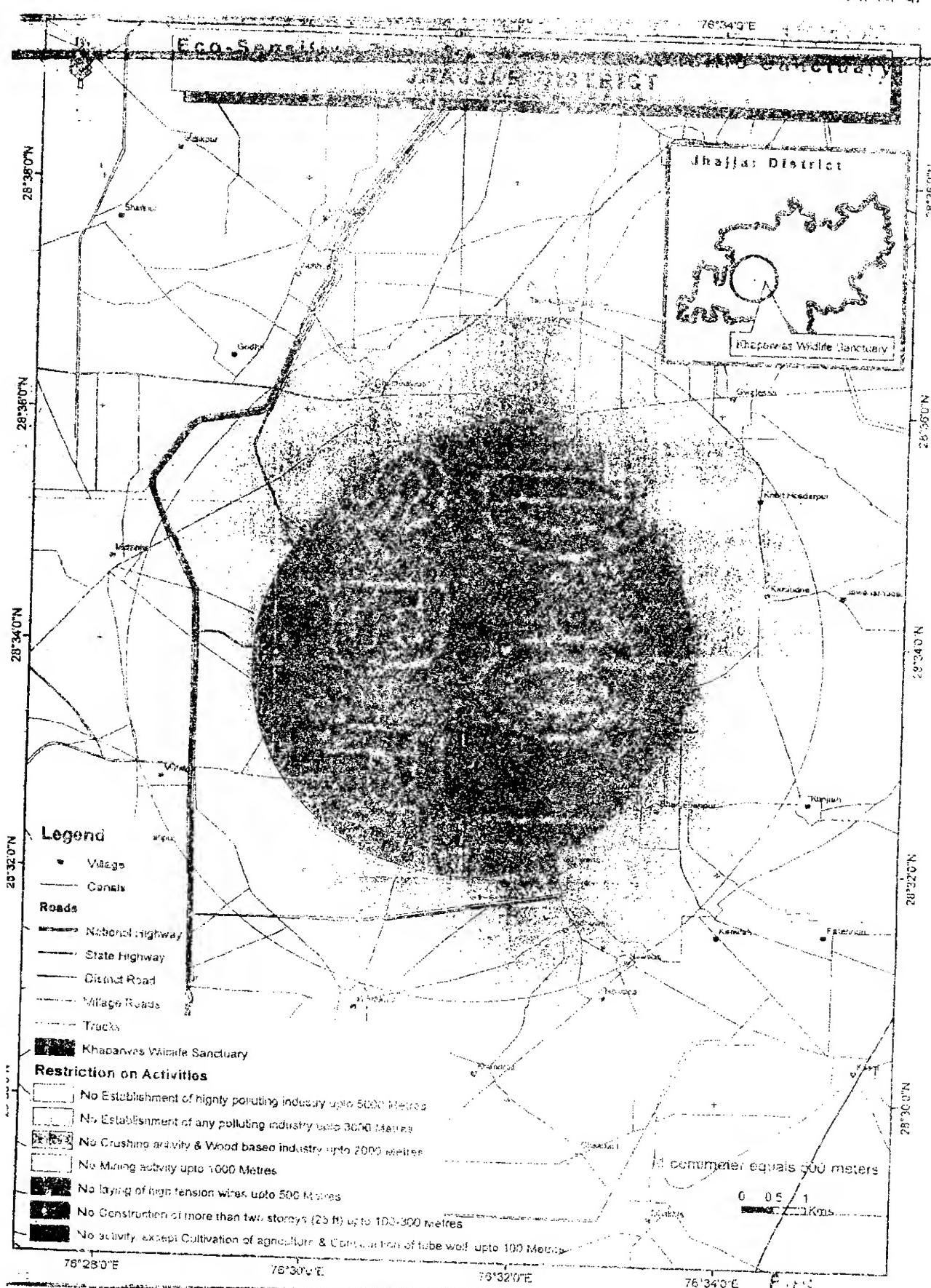
५. मानीटरी समिति-

- (1) बन्दीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन को मानीटर करने के लिए मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करती है ।
- (2) मानीटरी समिति दस से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और मानीटरी समिति का अध्यक्ष ऐसा विद्यात व्यक्ति होगा जिसको सिद्ध प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों की समझ हो तथा अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

- I. उप वन पालक (वन्य जीव), झाझर सदस्य-सचिव ;
 - II. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ; सदस्य
 - III. पर्यावरण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यस्त गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; सदस्य
 - IV. प्रादेशिक अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रटूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़; सदस्य
 - V. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार ; सदस्य
- (3) मानीटरी समिति की शक्तियां और कृत्य केवल इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन तक निर्बंधित होंगे ।
- (4) ऐसे क्रियाकलापों की दशा में, जिनमें पूर्व अनुमति या पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है, ऐसे क्रियाकलाप राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए) को निर्दिष्ट किए जाएंगे जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2007 के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।
- (5) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार की अपेक्षाओं पर आश्रित रहते हुए उसके निष्कर्षों में सहायता करने के लिए संबद्ध विभागों या संगठनों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती ।
- (6) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद काइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और वन मंत्रालय को 31 मार्च तक अपनी वार्षिक की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर मानीटरी समिति के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने निदेश देगा ।

[फा. सं. 30/1/2008-ईएसजेड]
डॉ. जी. वी. सुब्रह्मन्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपायक



NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2009

S.O. 1400(E).—WHEREAS, the Khaparwas Wildlife Sanctuary (about 80 kms from West of Delhi) attracts a large number and variety of migratory birds, and situated at a distance of about 1.5 km from Bhindawas Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

AND WHEREAS, the Central Government proposes to notify the area up to five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary enclosed within the boundary described below in the State of Haryana as 'Eco Sensitive Zone' (hereinafter called as the Eco Sensitive Zone) in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and for that purpose hereby publish this notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, or electronically at e-mail address: envisect@nic.in.

DRAFT PROPOSALS

1. Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

(i) The said Eco-sensitive Zone is the area upto five kilometers from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary situated in the Jhajjar District of Haryana between $28^{\circ} 30' 00''$ to $28^{\circ} 38' 00''$ North latitude and between $76^{\circ} 28' 00''$ to $76^{\circ} 38' 00''$ East longitude and the map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages falling within five kilometers distance of the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary in the Eco-sensitive Zone are as follows:

Chhuchhakwas, Marot, Kheri Hosdarpur, Karaudha, Sahajahanpur, Chadhwana, Redhuwas, Mundas, Dhani Islamgarh, Azadnagar, Khaparwas, Bahalgarh, Bambulia, Khetawas, Koyalpuri, Bilocpur, Bhindawas, Surajgarh, Nawada.

(ii) All activities in the Khaparwas Wildlife Sanctuary are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone:-

- (i) A Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette and submitted for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, Government of India.
- (ii) The Zonal Master Plan shall be prepared with due involvement of all concerned State Departments, such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipal and Revenue Department and the Haryana State Pollution Control Board for integrating environmental and ecological considerations into it and shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (iii) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing village settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and change of land use from green uses such as orchards, horticulture areas, agriculture parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of agricultural lands maybe permitted to meet the residential needs of the existing local residents together with natural growth of the existing local populations, without the prior approval of the State Government.
- (iv) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Monitoring Committee for any decision to be taken by them including consideration for relaxation.
- (v) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of traffic.
- (vi) Pending the preparation of the Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone and approval thereof by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, all new constructions shall be allowed only after the proposals are scrutinized and apptoved by the Monitoring Committee as referred to in paragraph 4 and there shall be no consequential reduction in Forest, Green and Agricultural area.
- (vii) The State Government shall prescribe additional measures, if necessary, in furtherance of the objectives and for giving effect to the provisions of this notification.

3. Regulated or restrictive activities in the Eco-sensitive Zone -

(a) Industrial Units:-

- I. No new wood based industry shall be set up within two kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.
- II. No new polluting industry shall be set up within three kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.

- III. No new highly polluting industry shall be set up within five kilometers from the boundary of the Khaparwas Wildlife Sanctuary.

(b) Construction Activities:-

- I. From the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary upto a distance of one hundred meters, no new construction of any kind shall be allowed except tube well chamber of dimension not more than one thousand cubic inches.
- II. In the area falling between one hundred meters to three hundred meters from the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary, construction of any new building more than two storeys (twenty five feet) shall not be allowed.
- III. From the boundary of Khaparwas Wildlife Sanctuary to a distance of five hundred meters, laying of new high tension transmission wire shall not be allowed.

(c) Quarrying and Mining:-

- I. Mining up to one kilometer shall not be allowed from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary.
- II. Crushing activity upto two kilometers shall not be allowed from the boundary of the protected area of Khaparwas Wildlife Sanctuary.

(d) Trees:- Felling of trees on forest and revenue land shall be subject to the approved management plan by the Government or an authority nominated for that purpose.

(e) Water:-

- (i) Extraction of ground water shall be permitted only for the bona-fide agricultural and domestic consumption and sale of ground water shall be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board.
- (ii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.

(f) Noise pollution:- The Environment Department or the State Forest Department, Haryana shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise in the Eco-sensitive Zone.

(g) Discharge of effluents:- No untreated or industrial effluent shall be permitted to be discharged into any water body within the Eco-sensitive Zone and treated effluent shall meet the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(h) Solid Wastes:-

- (i) The solid waste disposal shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 and the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.
- (ii) The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture and the inorganic material may be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

4. Monitoring Committee -

(1) Under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee to monitor the compliance with the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall consist of not more than ten members and the Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues and the other members shall be:-

- I. Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Jhajjar as the Member Secretary;
- II. a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India; Member
- III. one representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India; Member
- IV. Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board, Bahadurgarh; Member
- V. senior Town Planner of the area; Member

(3) The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification only.

(4) In case of activities requiring prior permission or environmental clearance, such activities shall be referred to the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), which shall be the Competent Authority for grant of such clearances as per the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, dated the 14th September 2007.

(5) The Monitoring Committee may also invite representatives or experts from concerned Departments or Associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Chairman or Member Secretary of Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 for non-compliance of the provisions of this notification.

(7) The Monitoring Committee shall submit its annual action taken reports by the 31st March of every year to the Ministry of Environment and Forests and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give its directions to the Monitoring Committee from time to time for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 30/1/2008-ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

ANNEXURE A

